छग व मप्र का प्रमुख पाक्षिक

डाक पंजीयन क्रमांक म.प्र./भोपाल/388/ 2021-23,
आर.एन.आई. नं. एम.पी.एच.आइ.एन. /2000/1225
पोस्टिंग दिनांक-प्रत्येक माह की 14-15 एवं 29-30

मध्यप्रदेश

लोक जतन

संस्थापक संपादकः शैलेन्द्र शैली

वर्ष : पच्चीस अंक : चौबीस पृष्ठ 16 नई सदी का नया अखबार 16 से 31 दिसम्बर 2024 मूल्य 7 रुपए 50 पैसे

जनता आकर डटी तब फर्जी नियुक्तियां रुकीं

राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित

अमरकंटक। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक - पहले की तरह इस बार भी नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती में घोटाले की पूरी तैयारी थी। इस तरह के कारनामो के लिए कुख्यात कुलपति का कार्यकाल 5 दिसंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा था और जाने के पहले अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में नॉन टीचिंग भर्ती करने की उन्होंने ठान ली थी। इस भर्ती के परीक्षा केंद्र रायपुर और बिलासपुर शहर में बनाया जाना भी कई तरह की आशंकाओं की तरफ संकेत कर रहा था। खास इलाके से एक खास राजनीतिक संबद्धता के लोगो को इस भर्ती में भरा जाना लगभग तय किया जा चुका था।

इस कुलपति के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को लेकर अनेक बार सवाल उठे हैं। पूर्व की एचडी भर्ती में इस प्रकार के घोटाला सामने आया था और कुलपति के सगे संबंधी एवं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ख़ास नाते रिश्तेदारों का पीएचडी भर्ती में चयन किया जा चुका था। विद्यार्थी और कर्मचारी सबूत गिनाते हुए बताते हैं कि गोरखपुर के किसी कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले श्रीप्रकाशमणि त्रिपाठी को सीधे उठाकर इस आदिवासी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनाये जाने के पीछे उनकी एकमात्र योग्यता खाँटी संघी होना था और इस नाते अपने पूरे कार्यकाल में इसने दोनों काम किये; यूनिवर्सिटी को संघियों से भरा और भ्रष्टाचार का घड़ा भी लबालब भरा। पिछली 5 वर्षों में अनारक्षित पदों की 110 नियुक्तियों में अपने जिले के अपने सजातीय लोगों को उनके गाँवों से लाकर सीधे नियुक्त किया। बिहार में आर एस एस की प्रचारकी करने वाले को बिना नेट और दूसरी बाध्यकारी योग्यता शर्तों के पूरा न करने पर भी सीधे शैक्षणिक स्टाफ में भर्ती कर दिया। अपने विशेष कर्तव्य अधिकारी - ओ एस डी - के पद पर भी गोरखपुर के किसी बी डी ओ को लाकर बिठा दिया।

यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही संदेह के घेरे में आ गयीए क्योंकि कि इस से पूर्व में सहायक प्राध्यापक की भर्ती विश्वविद्यालय कैंपस में हुई थी, लेकिन नान टीचिंग भर्ती प्रक्रिया इतने बड़े कैंपस को छोड़कर बिलासपुर और रायपुर में आयोजित करवाई गयी। मजे की बात यह थी कि इसमें लगभग 5 हजार अभ्यर्थी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल थे जिनका परीक्षा परिणाम दो दिन के अंदर ही घोषित कर दिया गया। इससे साफ था कि वी सी 5 दिसम्बर को अपना कार्यकाल पूरा होने के पीला अपइ व्यक्तियों को नियुक्ति देकर जाना चाहते थे।

इस घोटाले के बारे में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो इलाके के अनेक संगठन इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी को घेर कर बैठ गए। दो दिनों तक चले इस प्रदर्शन को मध्यप्रदेश किसान सभा के जिला महासचिव दलवीर केवट, युवा आदिवासी नेता तथा पुष्पराजगढ़ की सीपीएम के सचिव रमेश सिंह परस्ते, किसान सभा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह राठौर, सीटू जिला अध्यक्ष रामू यादव, आदिवासी युवा संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.रोहित सिंह मरावी, आदिवासी छात्र संगठन के अध्यक्ष वास्को दा गामा ने नेतृत्व और समर्थन दिया। इस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम सिंह उर्फ चिंटू, लोकेश सिंह मार्को (कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि) और कई सामाजिक संगठनों, किसानों, मजदूरों और स्थानीय निवासियों की भी सक्रिय भागीदारी देखी गई।

विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी गैर-शैक्षणिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।

बढ़ते दबाव का सामना करते हुए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, बल्कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी करने की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग पर भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी 16-सूत्रीय मांगों पर आगे बातचीत की और त्वरित कार्रवाई का वादा किया।

हाईकोर्ट ने खारिज किया न्यूनतम वेतन पर स्टे

प्रमोद प्रधान

इंदौर/भोपाल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कारखाना मालिकों की मिलीभगत से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण में किये जा रहे महाघोटाले के खिलाफ सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के मैदानी व कानूनी संघर्ष की शुरुआती जीत के रूप में पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरों के भुगतान पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ द्वारा 7 मई 2024 को दिये स्थगन आदेश को उसी खण्डपीठ द्वारा 3 दिसम्बर 2024 को खारिज किये जाने के रूप में सामने आयी है। इसका मतलब है कि अब उसी न्यूनतम वेतन दरो से भुगतान करना होगा जिसे भाजपा सरकार से मिलीभगत करके उद्योग घरानों ने रुकवा दिया था। अब न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से अब तक के एरियर्स के साथ बढी हुयी दरों से भुगतान का रास्ता खुल गया है। सीटू राज्य समिति की ओर से राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान ने 9 दिसम्बर को श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिख यह मांग की है कि पुनरीक्षण से तय बढी हुयी दरों के एरियर सहित भुगतान के सम्बन्ध में तुरन्त आदेश जारी कर श्रम विभाग के अमले के जरिये इसके भुगतान को सुनिश्चित किया जावे।

हर 5 साल में बढ़ाई जाने वाली न्यूनतम वेतन की दरें आखिरी बार 2014 इ पुनरीक्षित हुई थी - इसके बाद भाजपा सरकार ने इसे किया ही बही। सीटू ने इसके लिये संघर्ष किया तब जाकर इसके दबाव में अक्टूबर 2023 में दरें पुनरीक्षित कर 1 अप्रैल 2024 से दरें लागू करने के आदेश तो जारी कर दिये लेकिन इरादे उसे लागू करने के नहीं थे। कारखाना मालिकों के संगठनों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के लचर रवैये व मिलीभगत से न सिर्फ स्थगन मिल गया बल्कि उसके आधार पर श्रमायुक्त कार्यालय ने कम दरों के भुगतान हेतु नये आदेश भी जारी कर दिये।

इस स्थगन को लम्बा खीचते चले जाने की रणनीति में प्रदेश सरकार व उसके श्रम विभाग की भूमिका तब और उजागर हो गयी जब 31 जुलाई को न्यायालय में पेशी के दौरान उप श्रमायुक्त ने यह प्रस्ताव रख दिया कि कारखाना मालिकों की याचिका में रखी गयी मांग के सम्बन्ध में सरकार विचार कर संशोधित प्रस्ताव लाने के लिये तैयार है। इस पर न्यायालय ने दो माह का समय सरकार को देते हुये स्थगन को जारी रखा। चार माह के बाद भी न तो कोई वैकल्पिक प्रस्ताव आया और न ही इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये न्यूनतम वेतन सलाहकार मंडल की बैठक की। कारखाना मालिकों की इस मजदूर विरोधी जुगलबंदी के खिलाफ कानूनी मोर्चे पर सीटू इंटरवीनर के रूप में शामिल हुई और उसकी तरफ से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने मजदूरों का पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश समाप्त कर प्रकरण पर सुनवाई जारी रखने का आदेश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में श्रमिक पक्ष भी प्रभावित पक्ष है। इसलिये इस प्रकरण में जो श्रमिक पक्ष इंटर विनर के रूप में है उन्हें भी पक्षकार माना जावेगा। उन्हें नई याचिका प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी। इसके आधार पर सीटू अब नवम्बर 2019 से अब तक के एरियर का भुगतान, न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के दौरान की गयी हेराफेरी को दुरुस्त करने के साथ वर्ष 2024 की न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करने के लिये सरकार को निर्देश देने सम्बन्धी बिन्दु भी रखेगी। इस कानूनी लड़ाई को मुस्तैदी से लडने के साथ मैदानी रूप से संघर्ष को भी तेज करेगी।

संपादकीय

वे रोशनियाँ, जिन्होंने अंधेरों को कामयाब नहीं होने दिया

इन दिनों जब राजनीतिक दलों में बुजुर्ग होते हुए नेताओं को सिराने और अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी बनाकर कोने में बिठाने का आम रिवाज बन चुका है उन दिनों में एक पार्टी ऐसी भी है, जो उम्र के चलते देह से अशक्त हो चले अपने पुरोधाओं को न सिर्फ याद करती है बल्कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्हें आदरपूर्वक अपने सम्मेलन में बुलाती है। ऐसे ही एक राजनीतिक दल सी पी आई (एम) का राज्य सम्मेलन बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि इंदौर के महू, जिसे अब डॉ.अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, में 15 से 17 दिसम्बर में होने जा रहा है। इसमें उन वरिष्ठों को अभिनंदित किया जाएगा जिन्होंने अपनी जिन्दगी का एक बड़ा और बेहतरीन हिस्सा बहरों को सुनाने के लिए मूकों को आवाज देने, शोषण आधारित व्यवस्था द्वारा थोपे गए अलगाव को जुड़ाव में बदलने, बिखरों को संगठित करने, कातरता में फैले हाथों को गुस्से में तनी मुट्ठी और हताशा को उत्साह में तब्दील कर देने में खर्च कर दिया। ये वे रोशनियाँ हैं जिन्होंने किसी सूरज का इंतजार करने की बजाय जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन की और अंधेरों के नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया।

इस बार जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनमें **जुगल किशोर पिप्पल** हैं जो लगभग युवा अवस्था में ही जिसे अच्छी खासी कहा जाता है उस सरकारी नौकरी को छोड़कर देश को बेहतर बनाने की लड़ाई में कूद गए और अभी तक इतने युवतर हैं कि कुछ साल पहले पुलिस ने उन्हें रेल की पटरी उखाड़ कर कंधे पर उठाकर ले जाने का आरोप लगाने लायक समझा और महीनों तक जेल में रखा। **शेख गनी** हैं जिन्होंने दूर महाराष्ट्र से आकर न सिर्फ उस महकमे में जहाँ वे काम करते थे जगार की पुकार लगाई बल्कि बाकियों को भी बाखबर और सजग किया, उन्हें असली साहित्य से अवगत कराया; सच बताने वाले ऐसे ही साहित्य को लोगों को पढ़ाने के जुर्म में गिरफ्तारी तक झेली। 90 पार कर रहे **वकार सिद्दीकी** हैं जिन्होंने न सिर्फ उर्दू अदब में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले अदीबों की तरबियत की बल्कि कम्युनिस्ट आन्दोलन की दो पीढ़ियों को निखारा और लायक बनाया, ऐसा करते करते जेलें भी भुगतीं। **रामप्रकाश त्रिपाठी** है जिन्होंने सरकार उलट देने वाले साठ के दशक के छात्र आन्दोलन की अगुआई करते, गिरफ्तारियां सहते हुए जो तेवर अख्तियार किये, जो रास्ता चुना उस पर हमेशा अडिग रहे और साहित्य, कला, संस्कृति में न जाने कितनों का नजरिया साफ किया, हाथ पकड़ कर ऊंची पायदानों पर पहुंचाया। मालिक के नाम से पुकारे जाने वाले **एस पी शर्मा** हैं जो कभी शांत नहीं बैठे, मालवा से लेकर महाकौशल तक में मैदानी संघर्षों में भूमिका निबाही, सीटू के कोषाध्यक्ष और लोकजतन के प्रबंधक रहते हुए राज्य केंद्र को भी कामकाज का सलीका और शऊर सिखाया। **एस सी जैन** है जिन्होंने कोयला श्रमिकों के आन्दोलन में नेतृत्व की नई कतारें तो हर तरह से शिक्षित प्रशिक्षित की ही, अपनी कविताओं से संवारा भी। खुद एक उदाहरण पेश किया कि मार्क्सवाद की विचारधारा से लैस मजदूर नेता कितनी नि:स्वार्थ निस्पृहता के साथ काम करते है। दूसरों की तरह अपने घर नहीं बनाते मेहनतकशों के आँगन रोशन करते हैं। **रामलल्लू गुप्ता** हैं जिन्होंने अन्धेरा दूर करने के लिए खुद चिराग बनने का रास्ता चुना, किसानो और विस्थापितों के लिए लड़ते हुए नौकरी गंवाई, गोलीकांड सहित हर तरीके का दमन झेलते हुए अपने परिवार के साथ मिलकर मुश्किलें सहीं, मगर संघर्ष नहीं छोड़ा; सीधी सिंगरौली के हजारों आदिवासियों को जमीन दिलाई और उस पर काबिज रहने का हौंसला और संगठन दिया। **नारायण भास्कर** हैं जिन्होंने नौकरी में रहते हुए भी और उसके बाद भी अपने घर से दूर अकेले रहकर और व्यौहारी से लेकर अमरकंटक की पहाड़ियों को कभी साईकिल तो कभी मोटर साईकिल से नापते लांघते हुए लाल झंडे को लहराया, अनेक कन्धों तक उसे पहुंचाया। **प्रेमाबाई** हैं; पुराने शहडोल जिले के शानदार आदिवासी आन्दोलन की तीन माँओं में से एक मझिलिया बाई की बेटी, जिन्होंने अत्यंत गरीबी में अपने भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी और खेती किसानी की हाड़ तोड़ मेहनत मजूरी के बीच से भी समय चुराकर अपनी सक्रियता से ऐसे आन्दोलन संगठित करने में भूमिका निबाही जिनमें तप कर निकले आदिवासियों ने सामन्तों और उनके चाकरों के आगे झुकने की बजाय उनकी आँखों में आँखें डालकर देखना सीखा।

इन सबके आगे कामरेड का संबोधन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कई बार कुछ विशेषण और सर्वनाम संज्ञा बनते हुए समानार्थी बन जाते है; ये ऐसी ही शख्सियतें हैं जो इस भरोसा दिलाने वाले संबोधन का पर्यायवाची बन चुकी है। ये प्रतीक भर हैं; जिस लाल झंडे के नीचे ये जीए और जीना सिखाया उसके पास ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व है, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कबीर के कहे 'जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ' को जीकर चरितार्थ किया है।

इस घनघोर बाजारू और व्यक्तिवाद की चरम संक्रामकता के दौर में ये ऐसा क्यों और कैसे कर सके? इनके साथ और इनके बाद के इन जैसे अब भी कैसे उसे जारी रखे हुए हैं? उसकी वजह यह है कि गरीबों के लिए तन मन धन सब झोंक देने वाले ये लोग सोच और विचार के मामले में बहुत धनी और रईस हैं। इनके पास वह विचार है जिसे वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। जो इन्हें दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ही नहीं देता उसे बदलने का रास्ता भी दिखाता है। इनके पास संगठन की वह विधा, जनवादी केन्द्रीयता है, जिसने अब तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उन्हें संभव बनाया। जिसने इन्हें सिखाया कि किस तरह व्यक्ति से ऊपर समाज का हित होता है, कि जीवन की सार्थकता का पैमाना निजी सहूलियतें बढाने के लिए जुटाई गयी सुविधा या सम्पदा नहीं, समाज को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में भुगती गयी विपदाओं से जूझने में की गयी कुर्बानियां हैं।

ये बीज हैं जिन्होंने खुद को रोपा है ताकि दुनिया को चंद भेड़ियों की खुराक बनने वाले बंजर को इतिहास के कूड़ेदान में धकेल कर हरियाली लहलहाई जा सके; जब तक इस तरह के बीज है तब तक वसंत की आमद तय है, दुनिया का बदलना और जैसी है उससे बेहतर होना निश्चित है।

व्यंग्य

वीरेन्द्र जैन

सत्य की हत्या का युग

दुनिया की जितनी नैतिकताएं हैं, सब में एक सन्देश प्रमुख रूप से आता है, और वह है सत्य बोलो।

.....और जितनी भी कथित 'राजनीतियां' हैं, उनमें जो प्रमुख तत्व आता है, वह होता है सार्वभौमिक सत्य को छुपा कर अपना सत्य थोपो। कह सकते हैं कि एक लेबल पै कई लेबल लगा देते हैं लोग। बाजारवाद के इस युग में अपने अपने सत्य को बहुत शोर शराबे के साथ बेचते हैं। इसमें कई तरह के काम्बीनेशन भी आने लगे हैं। कोई अपने सत्य को जाति में लपेट कर बेचता हुआ मिल जाता है तो कोई धर्म में लपेट कर ग्राहकों को यह कहते हुए टिपा रहा है कि असली पुराना और विश्वसनीय माल यही है। इस बेचा बेची के शोर में सार्वभौमिक सच की आवाज कहीं सुनी ही नहीं जा रही। यों तो सब मानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है किंतु सूरज और पूरब पर मतभेद हैं। डुप्लीकेट माल बनाते बनाते चीन ने तो अपना नकली सूरज भी बना लिया है। कुछ दिनों में वह उसका एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। जिसको जितने बड़े पावर के सूरज की जरूरत होगी वह उतने बड़े सूरज का आर्डर दे देगा और और सिक्योरिटी भी देगा कि इसे कोई भक्ष भी नहीं कर सकता।

'विज्ञापन व्यापार का साधन है'। यह वाक्य कभी अखबार आदि में देखने को मिला करता था किंतु अब तो विज्ञापन ही अखबार का संसाधन हो गये हैं। खबरें भी इसलिए ही 'निर्मित' की जाती हैं ताकि विज्ञापन से सराबोर पन्ने घर घर में डलवाये जा सकें। कभी मुखपृष्ठ अखबारों की जान हुआ करते थे जिन पर छपी खबरों को चिल्ला चिल्ला कर हाकर रेलवे प्लेटफार्म या बस स्टेंडों पर हाकर बेचा करते थे। अब तो हाल यह है कि बस स्टेन्ड पर एक हाकर चिल्ला रहा था ' इसी बस स्टेंड पर सत्रह को लूटा' हाकर की उद्घोषणा के प्रभाव में बस की प्रतीक्षा करते हुए एक यात्री ने अखबार खरीद लिया और पहले से लेकर अंतिम पृष्ठ तक अखबार खंगाल डाला किंतु जब खबर कहीं नहीं मिली तो उसने हाकर की तलाश में नजरें दौड़ायीं। हाकर तो नहीं दिखा किंतु दूर उसकी आवाज सुनायी दे रही थी ' इसी बस स्टेंड पर अठारह को लूटा- अठारह को लूटा '।

कभी कहते थे कि कानों सुना झूठ और आंखों देखा सच , इसलिए जब विजुअल मीडिया आया तो लगा था कि अब सच सामने दिखेगा किंतु अब तो झूठ तरह तरह के मेक-अप और रंगबिरंगे परिधानों में परोसा जाने लगा। नोटबन्दी के बाद एक मीडिया हाउस की एंकर ने दो हजार के नोट जारी होने की खबर के साथ साथ कहा था कि इस नोट में ऐसी चिप लगी है जिसे जमीन की सात पर्तों में छुपा कर रखने पर भी सेटेलाइट से पता लगाया जा सकता है। इस इतने बड़े झूठ को इतने आत्मविश्वास से बोलते हुये सुन कर लोगों में काला धन उजागर होने की उम्मीद उछालें मारने लगी थी। वे सोचने लगे थे कि अब तो 15-15 लाख कहीं नहीं गये। वही मीडिया हाउस अब अपने को नम्बर वन कहता है और उस झूठी एंकर की पहुंच देश के सर्वोच्च नेताओं तक है। ना किसी ने उस मीडिया हाउस का बहिष्कार किया और ना ही उस एंकर को कोई सजा ही मिली। वह नित्य नये नये झूठ परोस रही है।

स्वतंत्र संघर्ष जितने मजबूत होंगे, संयुक्त लड़ाईयां उतनी ही ताकतवर होंगी

किसान सभा की बैठक में बनी योजनाये

जितेंद्र आर्य

समूदन (ग्वालियर)। 'गायब खाद, नकली बीज, ढपोरशंख बनती मंडी, करंट मारती बिजली से लेकर छीजती जमीन, भू माफिया की लूट, कल्याणकारी योजनाओं में घपले ही घपले, और मंत्रियों, नेताओं का चाकर बने कलेक्टर से लेकर नीचे तक का प्रशासन, ऐसी स्थिति में संगठित होकर संघर्ष करना की किसान सभा की प्राथमिकता है, लड़े बगैर कोई अधिकार नहीं मिल सकते है। उक्त आव्हान अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने ग्वालियर की मध्य प्रदेश किसान सभा की विस्तारित जिला समिति को संबोधित करते हुए किया।

किसान सभा की ग्वालियर जिला समिति की या बैठक समूदन गाँव मे सम्पन्न हुई, इस बैठक में जिले भर से चुनिंदा किसान कार्यकर्ताओं ने हिस्सेदारी की। जिला अध्यक्ष तलविंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मध्यप्रदेश किसान सभा के महासचिव अखिलेश यादव ने कहा कि खाद का संकट, बिजली की मार, आवारा जानवरो से खराब होती फैसले, आदिवासी की जमीनों को हड़पे जाने के ज्वलंत मामलों पर प्रशासन उदासीन है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जमीन हड़पने, भू माफियाओं के साथ खड़े है ऐसे में पीड़ित किसानो को संगठित करते हुए उनके आन्दोलन तेज करने होंगे।

बैठक की शुरुआत में जिला महासचिव जितेंद्र आर्य ने विचारार्थ एजेंडा रखते हुए विस्तार से आगामी कार्य योजना का खाका रखा जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवारा जानवरों एवं खाद संकट का यदि दिसम्बर माह में समाधान नहीं होगा तो एक जनवरी से किसान सभा द्वारा सरकारी कार्यालयों पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ 31 दिसम्बर तक जिले भर में पुरानी सदस्यता का नवीनीकरण कर 10 हजार किसानों को संगठन की सदस्यता दिलाई जायेगी।

प्रदर्शन...

ग्वालियर जिले के डबरा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश किसान सभा जिला समिति ग्वालियर ने ग्राम सर्वा के निवासियों को सन् 1986 में आवंटित की गई जमीन पर बसाने की कार्यवाही करने की माँग की। इसके अलावा खाद का संकट दूर करे, आवारा जानवरों की रोकथाम करने, बाढ़ राहत की राशि अभी भी कई परिवारों को नही मिल पाई है, उसका भुगतान कराने आदि की मांगें भी की गयीं। किसान सभा के जिला महासचिव जितेंद्र आर्य, कुशवाह समाज के वरिष्ठ नेता सुग्रीव सिंह कुशवाह, ग्राम पंचायत सर्वा के सरपंच प्रेम नारायण द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौप कर समाधान न होने पर आन्दोलन की चेतावनी दी गयी।

युवा मजदूरों को जोड़ना और नेतृत्व में लाना प्राथमिकता पर लेगी सीटू

दिल्ली में हुई बैठक का संकल्प

पूषण भट्टाचार्य

नई दिल्ली। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) ने युवा श्रमिकों को बेहतर भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए उन्हें प्रेरित करने की जरूरत बताते हुए आंदोलन के भीतर युवा श्रमिकों को संगठित करने और ट्रेड यूनियनों के सभी स्तरों पर उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाते हुए प्राथमिकता के आधार पर उन्हें संगठित करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में संगठित क्षेत्र के युवा कामगारों की एक बैठक में सीटू महासचिव तपन सेन ने बताया कि भारत की कामकाजी आयु वर्ग की लगभग 76.4 प्रतिशत आबादी (15–59 वर्ष की आयु) 39 वर्ष से कम उम्र की है। स्पष्ट है कि युवा कामगार भारत के कार्यबल का तीन-चौथाई हिस्सा है। इसमें भी बड़ा अनुपात युवा महिला श्रमिकों का है। अत्याधुनिक ज्ञान और कौशल से लैस युवा श्रमिक आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सबसे आगे हैं वहीं अत्यधिक अनिश्चित और असुरक्षित रोजगार स्थितियों में हैं। जो कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा के घेरे में है। उन्होंने कहा कि इतिहास इन्ही युवाओं द्वारा क्रांतिकारी विचार, जंगी कार्रवाई और क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के उदाहरण दिखाता है।

सीआईटीयू की अध्यक्ष के हेमलता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 20 राज्यों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 200 से अधिक युवा कामगारों ने भाग लिया, जो रणनीतिक और आधुनिक उद्योगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें मध्यप्रदेश के सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, स्पिनिंग जैसे निजी क्षेत्रों तथा कोयला, भेल, एनएफएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों से सम्बन्धित यूनियनों के 31 युवाओं ने हिस्सा लिया। सीमेंट मजदूर नेता विक्रम सिंह व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की ओर से कोयला मजदूरों के नेता सूरज पांडेय इसमें बोले भी।

सीटू राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रधान ने इस बैठक के फैसलों की जानकारी दी और बताया कि अब क्षेत्रीय/औद्योगिक महासंघ स्तर के युवा श्रमिकों का सम्मेलन और विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के श्रमिकों के राज्य स्तरीय क्लस्टर आधारित सम्मेलन किये जायेगे। राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक युवा श्रमिकों हेतु एक सांगठनिक ढांचा विकसित करने की योजना भी बनाई जाएगी। इसी के साथ दिल्ली में एक विशाल राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय हुआ है जिसमें भविष्य की कार्रवाई के साथ राष्ट्रीय मांग पत्र को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।

संघर्षो का प्रवाह ही खोलता है नए रास्ते

सीधी इकाई का सम्मेलन

तिलवारी (सीधी)। सी पी एम की सीधी इकाई का सम्मेलन पार्टी के वरिष्ठ नेता बलजीत सिंह गोंड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन में आये पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए इकाई के प्रभारी बादल सरोज ने देश और उसकी जनता के आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों के दोनों आयामों के बारे में बताया और कहा कि बड़े महाकाय कारपोरेट घरानो की लूट की छीजन के पैसे के दम पर संसदीय प्रणाली, दलीय राजनीति और लोकतांत्रिक प्रतिरोध में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं । इसके असर से कराह रहे लोगों की एकता को तोड़ने के लिए नकली मुद्दों के आधार पर उनके एक हिस्से को उन्मादी बनाया जा रहा है तो बहुत बड़े हिस्से का ध्यान बांटने की तिकड़में रची जा रही हैं। मगर इतिहास गवाह है कि दमन कितना भी भीषण हो, तानाशाही कितनी भी जालिम हो स्थायी नहीं होती; जनता की शक्ति से अधिक निर्णायक कुछ भी नहीं होता और यह जनमुद्दों को लेकर शुर होकर राजनीतिक बदलाव तक जाने वाले संघर्षों का प्रवाह ही है जो सारे अवरोधों को लांघते तोड़ते हुए नए रास्ते खोलता है।

वरिष्ठ माकपा नेता कामरेड सुन्दरसिंह बघेल ने पुराने संघर्षों की याद दिलाते हुए उत्साहित किया और सक्रियता बढाने का आव्हान किया।

सचिव रिपोर्ट बलराज सिंह गोंड ने पढ़ी। अभियान, गतिविधियों, आन्दोलन को संघर्ष तक ले जाने और संगठन में बांधने पर चर्चा हुयी तथा आगामी समय के लिए कुछ उपाय तय किये गए ।

सम्मेलन ने 7 सदस्यीय समिति चुनी जिसमे कामरेड सुन्दर सिंह बघेल, बलराज सिंह गोंड, शिव कुमार, सत्यदेव, सुग्रीव केवट जयदेव सिंह शामिल है। एक स्थान महिला के लिए रिक्त रखा गया है। राज्य सम्मेलन के लिए 3 प्रतिनिधि औरर दो वैकल्पिक चुने गए।

उमरिया माकपा सम्मेलन सम्पन्न

उमरिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) उमरिया का आठवां सम्मेलन 6 दिसंबर को बिरसिंहपुर पाली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रमोद प्रधान मौजूद रहे। सम्मेलन अमृत लाल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में शुरू हुआ। निवर्तमान सचिव ऊषा विश्वकर्मा ने सचिव रिपोर्ट पेश की जिस पर प्रतिनिधियों ने चर्चा कर सर्व सम्मति से पारित की। सम्मेलन में 25 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इसके बाद पांच सदस्यीय नई कमेटी का निर्वाचन किया गया, जिसमें किशन कोल, समर सेन, दशरथ केवट, ऊषा विश्वकर्मा, अमृत लाल विश्वकर्मा शामिल है। समिति सदस्यों ने ऊषा विश्वकर्मा को सर्वसम्मति से सचिव चुना।

राज्य सम्मेलन हेतु 2 प्रतिनिधियों अमृत लाल विश्वकर्मा और दशरथ केवट तथा वैकल्पित प्रतिनिधि समर सेन व दर्शक प्रतिनिधि शिवबहादुर सिंह निर्वाचित किया।

सम्मेलन अभियान जारी

विशेष संवाददाता

महू। सीपीएम के राज्य सम्मेलन की तैयारियों के लिए अभियान जारी है।

माकपा राज्य सचिव जसविंदर सिंह की कई मीटिंग्स के बाद अभी नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमे भाग लेने राज्य सचिव मंडल सदस्य रामनारायण कुरारिया पहुँच गये हैं। उनके साथ इंदौर जिला सचिव अरुण चौहान, महू इकाई सचिव राजू झरिया भी इन सभाओं में शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र को अडानी-अंबानी के हवाले करने की साजिश

बीएचईएल भोपाल में बोले तपन सेन

पूषन भट्टाचार्य

भोपाल। देश के समूचे भेल संयंत्रों के अस्तित्व के लिए आने वाली चुनौतियों एवं पब्लिक सेक्टर विरोधी नीतियों के कारण बीएचईएल कर्मचारियों, सोसायटी श्रमिकों, ठेका श्रमिकों के अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात पर संघर्ष की योजना बनाने के लिए भेल की समस्त इकाईयों के सीटू यूनियन के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक 4 दिसंबर को भेल भोपाल में आयोजित हुई।

भेल की हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुमयम, झाँसी, विशाखापत्तनम, त्रिचनापल्ली, रानीपेट समेत भेल की इकाईयों की सीटू यूनियन के 30 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में भेल की सभी इकाईयों में संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को विकसित करने के साथ कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने, भत्तों को बढ़ाने, ठेका श्रमिकों का वेतन केंद्रीय स्तर पर किए जाने को लेकर संघर्ष की योजना पर चर्चा हुई।

बैठक में सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन व राष्ट्रीय सचिव आर करूमलयन सीटू अखिल भारतीय केंद्र से उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश सीटू के महासचिव व सीटू के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रधान ने की। सीटू भोपाल के जिला अध्यक्ष पी एन वर्मा भी बैठक में उपस्थित रहे। भेल कामगार ट्रेड यूनियन भोपाल के अध्यक्ष लोकेन्द्र शेखावत, महासचिव रंजीत सिंह तथा अन्य पदाधिकारी शाहिद अली, रंजीत सिंह, अशोक पटेल, कुलदीप मौर्य, विनय सिंह, सादिक खान भी बैठक में मौजूद रहे।

इस बैठक के निर्णयों व भावी चुनौतियों के सम्बंध में जानकारी देने व के लिए दिनांक 4 दिसंबर 2024 को शाम को पिपलानी स्थित भेक्टू सीटू यूनियन कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक रखी गयी, जिसमें सभी ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि तथा ठेका श्रमिकोण के प्रतिनिधि अच्छी संख्या में शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता लोकेन्द्र शेखावत ने व संचालन दीपक गुप्ता ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए सीटू राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन ने कर्मचारियों से आने वाले संघर्ष की तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने भेल के समक्ष चुनौतियों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि भेल अपनी गुणवत्ता से सौदा नहीं करता है पर प्रतिस्पर्धी निजी कंपनिया घटिया माल बेचकर बाजार पर कब्जा कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार इन निजी कंपनियों का संरक्षण कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दौर में समूचे सार्वजनिक क्षेत्र को चंद मुनाफाखोरों, खासकर अदानी-अंबानी के हवाले करने की साजिश चल रही है। जिसकी एक कड़ी के रूप में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाईपलाईन नामक कुख्यात योजना सामने आयी है।

तपन सेन ने कहा कि सीटू ने देश की तमाम ट्रेड यूनियनों को एकजुट कर इसका प्रतिरोध तेज किया है। उन्होंने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले के खिलाफ एकजुट संघर्ष पर जोर देते हुए कहा कि भेल की रक्षा स्थायी श्रमिकों और ठेका श्रमिकों के साझे संघर्ष से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भेल के स्थायी श्रमिकों के वेतन पुनर्निर्धारण के साथ ठेका श्रमिकों को राज्य स्तर के न्यूनतम वेतन की जगह केन्द्रीय न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग सीटू करेगी। इस कार्यकर्ता बैठक को सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान ने भी संबोधित किया।

माकपा की नीमच इकाई का सम्मेलन संपन्न

पंकज नागदा चुने गए सचिव

नीमच। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सातवां नीमच सम्मेलन 8 दिसंबर रविवार को संपन्न हुआ। एक दिवसीय सम्मेलन में नए कार्यकाल के लिए पंकज नागदा को जिला सचिव गया तथा सहायक सचिव कामरेड निरंजन गुप्त के नाम का प्रस्ताव सुनील शर्मा द्वारा रखा गया जिसे उपस्थित साथियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने सचिव द्वारा रखी गई रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्थिति पर कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका एवं किए गए आंदोलन और पार्टी जन संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी बात रखी।

आगामी कार्यकाल के लिए चुने गए सचिव पंकज नागदा द्वारा स्थानीय स्तर पर पार्टी की कमजोरी एवं उसे दूर करने के लिए कदम उठाने हेतु नए आंदोलन का निर्माण एवं सामयिक मुद्दों पर संघर्ष करने पर जोर दिया तथा पार्टी साहित्य एवं पार्टी के मुख्य पत्र को पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत बताई।

पार्टी के महु राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि भी चुने गए । समापन उद्बोधन कांग्रेस विजय बैरागी द्वारा दिया गया।

सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधियों का जमावड़ा नहीं होगा

जसविंदर सिंह

संयोग से जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 17वां राज्य सम्मेलन 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थलि महू में होने जा रहा है। तब प्रदेश और देश की सत्ताधारी पार्टी भी अपने सांगठनिक चुनावों में उलझी हुई है। उलझी हुई इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा का सदस्यता अभियान संपन्न हुआ है। भाजपा अगर अंधभक्तों की भीड़ न होती तो सदस्यता अभियान को लेकर ही न जाने कितने सवाल खड़े होते और नेतृत्व कटघरे में निरुत्तर खड़ा होता।

भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी घोषित कर चुकी है। अब उसके अपने दावे के अनुसार उसकी सदस्यता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता को पार कर चुकी है। वैसे कम्युनिस्ट पार्टियों और बुर्जुआ पार्टियों के बीच सदस्यता को लेकर कोई तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्रांतिकारी पार्टियों की सदस्यता का पैमाना अलग होता है। मगर भाजपा की कितनी हो गई है? इस पर चर्चा बाद में। पहले सदस्यता अभियान और मिस कॉल सदस्यता की हकीकत। कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर, कुछ ने तो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया में भी भाजपा के ढोल की पोल खोलते हुए कहा कि वे फलां पार्टी के सदस्य हैं। पदाधिकारी हैं। मगर उनके पास भी मैसेज आ गया है कि वे भाजपा के सदस्य बन गए हैं। इस तरह के मैसेज माकपा कार्यकर्ताओं के पास भी पहुंचे और उन्होंने इसका खंडन भी किया। मगर भाजपा की ओर से न कोई सफाई दी गई। न कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। उनकी चुप्पी ने यह साबित कर दिया कि मिस कॉल पार्टी की सदस्यता भी मिसिंग है।

अब फिर वही सवाल के कुल कितनी सदस्यता? भाजपा ने सदस्यता अभियान में दस करोड़ का लक्ष्य रखा था। इस फर्जीवाड़े को जोड़कर कितनी सदस्यता हुई? यह भाजपा ने अभी तक नहीं बताया है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि भाजपा ने अपना सदस्यता लक्ष्य हांसिल कर लिया है तो उसकी सदस्यता दस करोड़ हो गई है। यह उस फर्जीवाड़े सहित है, जो मिस कॉल के चलते बारे बारे बेनकाब हुआ है और जिसका भाजपा नेतृत्व के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन यह दस करोड़ भी सदस्यता भाजपा की वृद्धि का संकेत है या गिरावट का। क्योंकि पिछले सदस्यता अभियान के बाद भाजपा ने 11 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य हांसल कर लेने का दावा किया था। पिछले बार ग्यारह और इस बार दस। एक करोड़ सदस्यता गवां कर भाजपा इसे उपलब्धि मान रही है। मगर मीडिया भाजपा के साथ है। वह उसे ऐसे प्रश्न नहीं करेगा।

अब भाजपा के सांगठनिक चुनावों के चर्चे। चर्चा चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, राज्य अध्यक्ष का या फिर जिलाध्यक्ष का सवाल हो। हर जगह जिज्ञासुओं को एक ही उत्तर मिलता है कि देखते हैं संघ किस पर मुहर लगाता है। क्या यह लोकतंत्र की विडंबना नहीं है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने भाजपा को हर स्तर पर अपना नेतृत्व तय करने के लिए किसी दूसरे संगठन की ओर देखना पड़ रहा है। यह दस करोड़ सदस्य अपना अध्यक्ष या नेता तय नहीं करेंगे। तो क्या यह दस करोड़ सदस्य सिर्फ भीड़ हैं। सिर्फ अंधभक्त हैं। सही मायनों में यह फासीवादी दलों का असली चरित्र है। वहां नेता के पीछे भीड़ या भक्त तैयार किए जाते हैं। इसलिए भाजपा ने दिखावे के लिए अपने संगठन की निर्वाचन प्रक्रिया और हर स्तर पर निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। लेकिन भाजपा का निर्वाचन भाजपा को नहीं करना है। संघ को करना है। जो कहता है कि वह तो सांस्कृतिक संगठन है,उसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है।

और यकीन मानिये, जिस पार्टी में लोकतंत्र न हो, वह पार्टी लोकतंत्र की हिफाजित नहीं कर सकती है। पिछले दस सालों में लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा और संघ की ओर से होने वाले हमलों को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

मगर बात सिर्फ भाजपा की नहीं है। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी हाल ही में अपनी जंबो कार्यकारिणी घोषित किया है। कार्यकारिणी जंबो है। पदाधिकारियों और कार्यकारणी सदस्यों की सूची बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि सबकी एक साथ बैठक करनी पड़े तो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय छोटा पड़ जाएगा। मगर उसके बाद भी नाराजगियां हैं। कुछ का कहना है कि उनके लोगों को नहीं लिया गया है। कुछ यह आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नेता अपने गुट के लोगों को भर कर कब्जा कर रहे हैं। इस्तीफों के दौर के साथ ही मानमनोब्बल भी शुरू हो गया है। जब नेता ही आपस में रूठे हैं। जब नेताओं को अपने गुट को शामिल कराने की चिंता है तो वह पार्टी अपनी उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेगी, जिसका जनादेश उसे विधान सभा चुनावों में मिला है। सशक्त और सतर्क विपक्ष की भूमिका निबाहने की जिम्मेदारी।

वैसे जब कांग्रेस की बात करें तो मामला सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का नहीं है। पिछले कई सालों से जिला इकाईयों ने अपने पदाधिकारी और कार्य समितियों का गठन नहीं किया है। यह हास्यास्पद नहीं है कि पिछले विधान सभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आने के सपने देख रही थी। जनता का भाजपा विरोधी रुख देख कर उसके मुंह में लड्डू ही नहीं फूट रहे थे बल्कि मंत्री मंडल के गठन और विभागों के आवंटन को लेकर झगड़े भी हो रहे थे। मगर कांग्रेस के सेनापति बिना सेना के युद्ध लड़ रहे थे। अभी भी कांग्रेस बिना संगठन के खड़ी है और बिना संगठन, बिना भाजपा के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़े सत्ता हांसिल करने के शेखचिल्ली सपने देख रही है।

इन्हीं परिस्थितियों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन डा. अंबेडकर नगर महू में होने जा रहा है। यह सम्मेलन अचानक आयोजित नही हुआ है। इस सम्मेलन से पहले पार्टी की सबसे प्राथमिक इकाई पार्टी ब्रांच के सम्मेलन आयोजित हुए। उसके बाद तहसील और क्षेत्रिय स्तर के सम्मेलनों का आयोजिन हुआ। राज्य सम्मेलन से पहले सारे जिला सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है और जिला सम्मेलनों द्वारा राज्य सम्मेलन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि ही राज्य सम्मेलन में हिस्सेदारी करेंगे।

सम्मेलन सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधियों का जमावड़ा नहीं होगा। सम्मेलन में पिछले तीन सालों की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों का आकलन होगा। प्रतिनिधि राज्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की हां में हां नहीं मिलायेंगे। बल्कि वे अपने राय देंगे। जो नहीं हो पाया है उसके लिए नेतृत्व की आलोचना भी करेंगे। उसके बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सम्मेलन आने वाले तीन साल के लिए साल के लिए नए नेतृत्व और राज्य कमेटी का चुनाव भी करेगा और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी करेगा। आप अंतर तो समझ गए होंगे न?

क्या टी आई का काम सीपीएम का दफ्तर कब्जा कराना और अपराधियों को पालना ही है ?

सिंगरौली। थाना नवानगर और बैढन के टी आई का काम सिर्फ सीपीएम का चौथाई सदी पुराना दफ्तर खाली करवाना और अपराधियों को पालना ही है या जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वह भी है ? यह सवाल जिले के पुलिस अधीक्षक को दिए एक ज्ञापन में पूछा गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला- सिंगरौली का कार्यालय माजन-मोड, बैढ़न में 25-26 वर्ष से संचालित एवं है। इसे पार्टी द्वारा आम जनता से चंदा लेकर राम जी शाह की छत के ऊपर उसकी मर्जी से निर्माण कराया गया था, अब कुछ दिनो से वह राजनीतिक दबाव में इसे खाली कराना चाहता है। 25 नवम्बर को पता चला कि उसने ताला तोड़ कर नया ताला लगा दिया है। इस बारे में जब रिपोर्ट की गयी तो टी आई ने कुछ भी नहीं किया मगर जब वरिष्ठ माकपा नेता रामलल्लू गुप्ता की अगुआई में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोबारा से अपना ताला लगा दिया तो यह टी आई खुलकर इस अवैध कार्यवाही करने वाले के पक्ष में उतर आया और माकपा नेताओं को धमकी भरे फोन करवाने लगा।

सिगरौली एस पी से पूछा

टी आई की इस हरकत के खिलाफ माकपा राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने भोपाल में पुलिस महानिदेशक को भी अवगत कराया । इस सहित कई अन्य मामलों को लेकर माकपा ने पुलिस अधीक्षक के सामने धरना प्रदर्शन किया था।

माकपा जिला सचिव लालबाबू कुशवाह द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में इस पुलिस अफसर की भ्रष्ट, लापरवाहाना तथा आपराधिक हरकतों के अनेक प्रकरण दर्ज कराये गए जिनमे थाना नवानगर एवं बैढ़न में पदस्थ टी0आई0 एवं उप निरीक्षक द्वारा बिना पैसे लिये जॉच नहीं करना, जॉच में देरी करना, थानों के अन्तर्गत रेत, मिट्टी उत्खनन का अवैध परिवहन एवं कोयला, कबाड़, डीजल की चोरी जोरो से करवाना, गंभीर अपराधो में कार्यवाही न करते हुए क्षेत्रीय जनता का शोषण के साथ -साथ उनपर धन उगाही का दबाब डालकर उन्हे लंबे समय तक थाने का चक्कर काटने पर मजबूर किया जाना, शिव प्रसाद शाह को लोगो ने सुपर बस्ती अमझर के पास मार कर फेक दिए जाने जैसे मामले में कार्यवाही न करना, सोहवाती पति रामसखा नामदेव तथा दीप कुमार प्रजापति निवासी माजनखुर्द द्वारा की गयी उत्पीड़न की रिपोर्ट, सुरेन्द्र प्रसाद बियार ग्राम भरूहा को अमलोरी के सी आई एस एफ के जय प्रकाश यादव द्वारा उल्टा लटका कर मारा पर कुछ न करना, मो0 नईन के आवास बी-185 में चोरो के द्वारा एक लाख रूपये नगद, गैस सिलेन्डर, मिक्सर ग्राईडर, प्रेस, मोबाईल चार्ज सहित अन्य समान चुरा लेने की शिकायतों पर कुछ नहीं करा वहीं वास्तविक अपराधियों को बचाने हेतु गरीब व कमजोर व्यक्ति पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिखावा करना आदि शामिल हैं।

ज्ञापन में कामरेड रामलल्लू गुप्ता को फोन पर धमकी दिए जाने के मामले की भी जांच की मांग की है । यह फोन टी आई के नाम पर थाने में बुलाने के सन्देश के साथ आया था ।

इन सवालों को लेकर माकपा के धरना प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सीएसपी ने जांच करने के लिए समय माँगा है ।

जमीन अधिग्रहण के 31 साल बाद मिला भू-विस्थापित बृजमोहन को नियुक्ति पत्र,

आंदोलन के दबाव में अब तक मिली है 20 लोगों को स्थाई नौकरी

कुसमुंडा (कोरबा)। जमीन के बदले रोजगार की मांग कर रहे भूविस्थापित किसानों के आंदोलन को एक और कामयाबी मिली है। 2 दिसम्बर को कुसमुंडा कोयला खदान बंदी के बाद बने दबाव से आनन-फानन में एसईसीएल के बिलासपुर मुख्यालय ने पुराने लंबित रोजगार प्रकरण मामले में एक और भू-विस्थापित बृजमोहन लाल को रोजगार देने के लिए एप्रुवल आदेश जारी किया, जिसके बाद कुसमुंडा महाप्रबंधक राजीव सिंह के अपने हाथों से उसे नियुक्ति पत्र थमाया। बृजमोहन के परिवार की जमीन का 1993 में एसईसीएल ने अधिग्रहण किया था और वह पिछले 31 सालों से रोजगार के लिए भटक रहा था। छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ द्वारा चलाए जा रहे अनवरत धरना प्रदर्शन के कारण एसईसीएल को इसके पहले 20 और लोगों को रोजगार देना पड़ा है। इस जीत से उत्साहित आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष को और तेज करने का फैसला किया है और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी विस्थापित परिवारों को रोजगार मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निश्चय किया है।

उल्लेखनीय है कि कुसमुंडा कोयला खदान विस्तार के लिए 1978 से 2004 तक जरहा जेल, बरपाली, दुरपा, खम्हरिया, मनगांव, बरमपुर, दुल्लापुर, जटराज, सोनपुरी, बरकुटा, गेवरा, भैसमा आदि गांवों में बड़े पैमाने पर हजारों किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस समय एसईसीएल की नीति भूमि के बदले रोजगार देने की थी। लेकिन प्रभावित परिवारों को उसने रोजगार नहीं दिया। बाद में यह नीति बदलकर न्यूनतम दो एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर एक रोजगार देने की बना दी गई। इससे अधिग्रहण से प्रभावित अधिकांश किसान रोजगार मिलने के हक़ से वंचित हो गए।

पिछले 1140 दिनों से छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के द्वारा %जमीन के बदले रोजगार% आंदोलन चलाया जा रहा है। ये दोनों संगठन जमीन अधिग्रहण के समय की नीति के अनुसार सभी प्रभावितों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं और इस मांग पर जोर देने के लिए वे कई बार कुसमुंडा खदान बंद, महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव तथा सीएमडी कार्यालय के अंदर भी धरना जैसे आंदोलन भी कर चुके हैं। खदान बंदी के दौरान किसान सभा नेता प्रशांत झा समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था।

बृजमोहन को नौकरी मिलने की खबर मिलते ही धरनास्थल पर इस जीत की खुशी में मिठाईयां बांटी गई। इस अवसर पर आयोजित सभा को छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत झा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान सभा का शुरू से मानना है कि जिनकी जमीन का एसईसीएल ने अधिग्रहण किया है, प्रत्येक खातेदार को स्थाई रोजगार मिलना चाहिए। एसईसीएल को इस जायज मांग को मानना पड़ रहा है। आंदोलन के दबाव में कम जमीन, डबल अर्जन और रैखिक संबंध के मामले में एसईसीएल को नियमों में बदलाव करना पड़ा है और 20 से अधिक भू-विस्थापितों को स्थाई रोजगार देने के लिए एसईसीएल को मजबूर होना पड़ा है। अब प्रबंधन के खिलाफ अर्जन के बाद जन्म के मामले में भी विस्थापितों के पक्ष में फैसला देने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा।

रोजगार एकता संघ के सचिव दामोदर श्याम और अध्यक्ष रेशम यादव ने कहा कि दमन के सहारे शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता है। जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे है, उन्हीं की जीत हुई हैं। धरना स्थल पहुंच कर बृजमोहन ने भी अपना रोजगार पाने के लिए आंदोलन के प्रति आभार व्यक्त किया।

पिपरिया में जनवादी लेखक संघ का वैचारिक आयोजन : पुस्तक चर्चा के साथ काव्य पाठ भी

पी सी रथ की रिपोर्ट

पिपरिया (कवर्धा)। छत्तीसगढ़ जनवादी लेखक संघ, कवर्धा जिला इकाई द्वारा वैचारिक कार्यक्रम कबिरा खड़ा बजार में तथा पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हायर सेकेण्डरी शाला पिपरिया के सहयोग से 8 दिसंबर को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में दुर्ग के दो साहित्यकारों बद्रीप्रसाद पारकर तथा कमलेश चंद्राकर की पुस्तकों पर चर्चा हुई।

बद्रीप्रसाद पारकर की पुस्तक 'धीरे-धीरे उतरे पार' पर लेखक एवं पत्रकार नीरज मंजीत ने आलेख पठन करते हुए कहा कि यह जीवनी पठनीय है, प्रेरक और संग्रहणीय भी। दुर्ग जिले के रचनाकारों ने लगातार साहित्य की दुनियां में नाम किया है। कवि एवं समीक्षक अजय चंद्रवंशी ने कहा कि केंवट समाज में जन्में लेखक बद्रीप्रसाद पारकर ने संघर्ष की गाथा को जिस ढंग से लिखा है, वह प्रशंसनीय है। समाज में निचले पायदान पर रहने वाले लोगों का जीवन संघर्ष कितना कठिन होता है, यह हम 'धीरे धीरे उतरे पार' पढ़कर जान पाते हैं।

कमलेश चंद्राकर की चार बाल कविताओं की किताब पर नरेन्द्र कुमार कुलमित्र ने कहा कि बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ सीखने लायक बातें इन किताबों में है। ये कविताएं गाई जा सकती हैं। इनमें संगीत सरल भी है। समीक्षक सुखदेव सिंह अहिलेश्वर ने कमलेश की पुस्तकों पर आलेख वाचन करते हुए हिन्दी की मजबूत बालगीत परंपरा के इतिहास पर बोलते हुए कमलेश चंद्राकर को इसी परंपरा का वर्तमान दौर का महत्वपूर्ण कवि कहा। जलेस के कोषाध्यक्ष और उपन्यासकार नंदन ध्रुव ने कहा कि आप पढ़ कर जीवन में अपनी दिशा में आगे बढ़ें, किंतु साहित्य को जीवन में महत्व देकर जीवन को सरस जरूर बना सकते हैं। साहित्य व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है। साहित्य से हम एकता, संघर्ष और उदारता का पाठ पढ़ते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष साहित्यकार डॉ. परदेशीराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ में जिला इकाइयों की सक्रिय भूमिका के संबंध में बताया। कवि समीक्षक, पत्रकार तथा जनवादी लेखक संघ के प्रदेश महासचिव पी.सी. रथ ने सभा को सम्बोधित करते हुए छात्र-छात्राओं के लिए कविताओं, कथाओं और अन्य कलाओं में भागीदारी को पढ़ाई के तनाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज के मोबाईल इंटरनेट युग में उनका इस्तेमाल ज्ञान और करियर को बेहतर मुकाम देने के लिए करने को उन्होंने उदाहरण सहित बताया। कवर्धा जिला जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष समय लाल विवेक ने स्वागत भाषण दिया। कमलेश चंद्राकर एवं बद्रीप्रसाद पारकर ने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताया तथा रचना-पाठ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य सतीश कुमार बंजारे को डॉ. परदेशीराम वर्मा, नंदन ध्रुव तथा पी सी रथ ने स्कूल लाइब्रेरी हेतु पुस्तकें भेंट की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार बंजारे ने कहा कि ऐसे वैचारिक कार्यक्रमों से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। छत्तीसगढ़ के चर्चित साहित्यकारों से मिलकर उनका रचना-पाठ सुनना इन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करेगा। सुखदेव सिंह,भागवत साहू, सात्विक श्रीवास्तव तथा विद्यालय की दो छात्राएं भावना देवांगन तथा सुहानी देवांगन ने स्वरचित रचनाओं का काव्य पाठ किया। संचालन भागवत साहू ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन विद्यालय परिवार की ओर से विनोद चंद्रवंशी द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में स्मिता वर्मा, दशरथ सोनी, नीतीश, प्रशांत शर्मा, संजय पराते, सोमप्रकाश वर्मा, संतराम थवाइत , रमेश चौरिया, राजाराम हलवाई, बृजेन्द्र श्रीवास्तव, प्रहलाद पात्रे, अश्विनी कोसरे, नारद चंद्रवंशी, चतुर चंद्रवंशी सहित क्षेत्र के प्रमुख रचनाकार, समाज सेवी, कलाकार भी साहित्य में रुचि रखने वाले छात्रा-छात्राओं के साथ उपस्थित थे।

भारत और बंगलादेश : सांप्रदायिक विभाजन से बचें

प्रकाश करात

बंगलादेश में हिंदुओं और बौद्धों जैसे अन्य अल्पसंख्यकों पर निरंतर हो रहे हमले व्यापक चिंता का विषय बने हुए हैं। एक जन आंदोलन के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यह अपेक्षा की जा रही थी कि उनके तानाशाही शासन के खत्म होने के बाद, बंगलादेश में एक कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरूआत होगी। बहरहाल, शुरू के कुछ दिनों की अफरा-तफरी में ही देश भर से कुछ हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमलों की रिपोर्टें आने लगी थीं। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद युनुस ने उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। लेकिन उसके बाद की पूरी अवधि में घटनाएं होती रही हैं। अभी तक हिंसा की कोई 2,000 वारदातें दर्ज हो चुकी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम नौ सदस्य मारे जा चुके हैं।

स्थिति में मौजूदा बिगाड़ तब आया, जब एक हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। चिन्मय कृष्ण दास पहले इस्कॉन (आइएसकेसीओएन) से जुड़े रहे हैं, लेकिन फिर वहां से उनको हटा दिया गया और अब वे ''सम्मिलित सनातनी जागरण जोत'' की अगुवाई कर रहे हैं। अगर वे उग्र किस्म के विचार व्यक्त भी कर रहे थे, तो देशद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बंगलादेश के राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करने का आरोप काफी भारी-भरकम दिखाई देता है। जब दास को अदालत में पेश किया गया और उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया गया, तो पुलिस तथा उनके अनुयायियों के बीच में झड़प हो गयी। भीड़ ने एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर (सरकारी वकील) पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह घटना यह दिखाती है कि इस वक्त सांप्रदायिक स्थिति कितनी भयावह है।

अंतरिम सरकार और उसके प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया, यह दावा करने के जरिए इन हमलों को कमतर करके दिखाने की ही रही है कि इन हमलों को बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट किया गया है। इसे उन्होंने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के खिलाफ जनता के रोष की अभिव्यक्ति के रूप में ही पेश करने की कोशिश की है। वे इस बंगलादेशविरोधी अभियान के पीछे, भारत सरकार का ही हाथ देख रहे हैं। इस्लामिक शक्तियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर तेज किए गए इन हमलों की अनदेखी करने की कोशिश करके युनुस के नेतृत्ववाली सरकार गलती ही कर रही है।

जो भारतविरोधी भावना वहां है, उसका कारण शेख हसीना निजाम के लिए मोदी सरकार का समर्थन रहा है और अब इस्लामिक तत्ववादी शक्तियां अल्पसंख्यकों पर हमले के आवरण के तौर पर, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। जमाते-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने और उसके नेताओं के जेलों से बाहर आने के साथ ''हिफाजते इस्लाम'' जैसे तत्ववादी संगठनों को हिंदुओं को निशाना बनाने और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की छूट मिल गयी है। शेख हसीना के शासन के वक्त भी इस तरह की तत्ववादी शक्तियां अल्पसंख्यकों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही थीं। बंगलादेश की अंतरिम सरकार और वहां की लोकतांत्रिक शक्तियों को पुरजोरी से और दृढ़ता के साथ, उन साम्प्रदायिक तत्वों से निपटना होगा, जो इस स्थिति में अपनी कट्टरपंथी राजनीति को स्थापित करने का अवसर देख रहे हैं।

भारत में भाजपा-आरएसएस तथा विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों का रुख, समुचित ढंग से स्थिति से निपटने में मददगार नहीं दिखता। सीमापार के हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में भौंडे तथा कुत्सापूर्ण प्रचार को, बंगलादेशी प्रशासन और लोकतांत्रिक हलके बंगलादेश की नयी राजनीतिक व्यवस्था को डराने-धमकाने तथा बदनाम करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। उग्र हिंदू ग्रुपों द्वारा कोलकाता, अगरतला तथा गुवाहाटी में बंगलादेशी कोन्सुलेटों के समक्ष आयोजित प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल की गयी कटुतापूर्ण भाषा ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

अगरतला में हुई वह घटना, जब ''हिंदू संघर्ष समिति'' के प्रदर्शनकारी बंगलादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन के परिसर में घुस गए और वहां संपत्ति की तोडफ़ोड़ की, बंगलादेश में भारतविरोधी भावनाओं को और तीखा ही करेगी। बंगलादेश के खिलाफ आगउगलू भाषणबाजी, बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ही खतरे में डालेगी।

ऐसे में अल्पसंख्यकों की रक्षा से संबंधित बंगलादेशवासियों को दिए जानेवाले भारतीय शासकों के उपदेशों को बंगलादेश की जनता तब संदेह की नजर से ही देखेगी, जब खुद उन्होंने अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करने तथा उन्हें सताने का एक बदतरीन रिकॉर्ड कायम कर रखा हो। बंगलादेश में जनमत, भारत के सर्वोच्च नेताओं द्वारा बंगलादेशियों के खिलाफ निरंतर की जानेवाली लफ्फाजी से भी प्रभावित हुआ है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में बंगलादेशियों की व्यापक घुसपैठ के बारे में झूठ बोला और कड़ी चेतावनियां दीं। इससे पहले वे इस तरह के घुसपैठियों को ''दीमक'' की संज्ञा दे चुके थे।

इन दोनों ही देशों में धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए आवश्यक है कि वे इस पर जोर दें कि विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति, दोनों देशों के हितों के लिए ही नुकसानदेह है। यह बंगलादेश में उन धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शक्तियों की जिम्मेदारी है-जिन्होंने शेख हसीना के तानाशाही शासन के खिलाफ संघर्ष किया है कि वे उठ खड़ी हों और इस बात पर जोर दें कि अल्पसंख्यकों के लिए देश सुरक्षित है और नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।

▶ लेखक-सीपीआई(एम) के पोलिट ब्यूरो सदस्य है।

अलविदा जावेद : इस दुनिया को हम तुम्हारे लायक बनाएंगे

सत्यम पाण्डेय

11 दिसम्बर को जब जहांगीराबाद कब्रिस्तान में जावेद अनीस को दफनाया जा रहा था तो वहां मौजूद एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसकी आँखें नम नहीं थीं। वहां बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग थे। लेकिन गैर मुसलमानों की संख्या उनसे बीस गुना ज्यादा थी। इतनी बड़ी संख्या में कब्रिस्तान में महिलाओं को देखकर लोग हैरत में थे। खुद जावेद के अब्बा ने आज उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने गए साथियों से कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे बेटे को भोपाल में लोग इतना प्यार करते हैं।

हम सब अपने प्रिय दोस्त जावेद अनीस को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। एक इतना प्यारा आदमी जिसने जितनी भी जिंदगी जी, इस दुनिया को बेहतर बनाने के काम में लगा रहा। लेकिन सियासत ने इस जिंदगी को इतना बदरंग कर दिया है कि इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान ने जिंदगी से पलायन का त्रासद विकल्प चुन लिया। हमेशा संजीदा रहने वाले व्यक्ति ने, हमेशा दोस्तों के बीच खुशनुमा रहने और दूसरों को खुश करते रहने वाले व्यक्ति ने अचानक समय के इस मोड पर खुद को इस दुनिया में मिसफिट पाया और खुद को खत्म करने का साहस कर लिया। यह न केवल इस सियासत पर, इस समाज पर एक झन्नाटेदार तमाचा है बल्कि खुद को उनका दोस्त कहने वाले हम लोगों के लिए भी एक गंभीर आत्मालोचना का मौका है। हम लोग हर बार इतने नकारा साबित क्यों होते हैं कि एक हंसता खेलता आदमी हमारे बीच से चला जाता है और उसके पहले जाने जरा भी भनक नहीं लगती। बाहर से एकदम ठीक लगने वाले व्यक्ति के अंतर्मन में समाज और राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही मनुष्य विरोधी प्रवृतियां, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा ने इतने घाव कर दिए होते हैं कि वह इस दुनिया को जीने लायक मानने से ही इनकार कर देता है और हमें कानों कान खबर भी नहीं होती।

जावेद, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में पैदा हुए और उच्चतर शिक्षा लखनऊ, दिल्ली और बैंगलोर में हासिल की। उन्होंने भारत में मदरसों के आधुनिकीकरण के विषय पर पीएचडी की थी। जावेद अपने विचारों में प्रगतिशील और वामपंथी थे और विगत 20 सालों से भोपाल में रहते हुए तमाम जनपक्षीय कार्यवाहियों का एक जरूरी हिस्सा होते थे। विगत एक दशक से हमारे देश में दक्षिणपंथी फासीवादी राजनीति के सत्ता में आने के बाद जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक माहौल देश में बन रहा था वे हम सब की तरह उससे बहुत परेशान थे। जनचौक में प्रकाशित उनके एक लेख में वे लिखते हैं।

'आज भारत अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, यह एक ऐसा संकट है जिसमें भारत का अतीत और भविष्य दोनों निशाने पर है. यह स्पष्ट रूप से देखा और समझा जा सकता है कि 2014 से इस देश की सत्ता ऐसा लोगों के हाथों में पहुंच गई है जो इस देश के भविष्य को ही नहीं बल्कि इतिहास को भी पूरी तरह से बदल देने के लक्ष्य के साथ हैं और इसके बदले देश पर एक ऐसे विचार को थोप रहे हैं जो पूरी तरह से एकांकी, विभाजक और प्रतिगामी है। यह केवल राजनीतिक संकट नहीं बल्कि इसमें समाज, संस्कृति और राजनीति सभी कुछ शामिल हैं. तो क्या भारत सभ्यता के संकट के दौर से गुजर रहा है?'

सभ्यता का यह संकट देश के हर अमनपसंद व्यक्ति पर भारी पड़ रहा है लेकिन जैसा उपासना ने मुझसे कहा था कि जब किसी का नाम मुसलमानों जैसा हो तो उसके लिए यह घातक होता है।

एक बहुत बड़े मानवता वादी और सेकुलर मित्र समूह होने के बावजूद जावेद को अपने जीवन में अनेक बार इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा था। उनको हर बार घर किराए पर लेने या खरीदने में सिर्फ इसलिए दिक्कत पेश आती थी कि उनका नाम जावेद है। किसी भी धार्मिक त्यौहार पर आजकल जिस तरह खुलेआम हिंसा और हथियारों का प्रदर्शन होता है, वह किसी को भी दहला सकता है। फिर एक मानवतावादी वामपंथी विचारक की तरह जावेद हर तरह की सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ के खिलाफ थे। वे हिंदुत्ववादी साम्प्रदायिक तत्वों के खिलाफ लिखते थे तो मुस्लिम सांप्रदायिकता भी लगातार उनके निशाने पर होती थी। इस तरह की पोजीशन से हम सब लोगों ने अपने अनेक पारिवारिक संबंधों को खोया है, जावेद ने भी खोया होगा। हम सबकी तरह जावेद ने भी एक दिन ये पाया होगा कि तमाम तरह के कट्टरपंथी और मनुष्य विरोधी समूह उनके खिलाफ हैं। ये सब बातें एकत्रित होती गई और जावेद ने अंतत: वह किया जो उनसे अपेक्षित नहीं था। यह विडम्बना है कि जानबूझकर दिया संदेश कि मानव अधिकारों के एक सशक्त योद्धा ने अपने जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का दिन ही चुना।

ऐसे नहीं होता दोस्त। आप एक लड़ाई में थे। इस दुनिया को और सुंदर, बेहतर और सबके रहने लायक जगह बनाने की लड़ाई, सबके लिए बराबरी, न्याय और गरिमा की लड़ाई। बीच लड़ाई में साथ छोड़कर नहीं जाया जाता। हम सब इस काम के लिए संकल्पित हैं और ऐसी दुनिया को बनाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे जहां फिर किसी जावेद को यह कदम न उठाना पड़े।

जिंदाबाद जावेद अनीस, आपकी लड़ाई जारी रहेगी;
तुम्हारी कब्र में हम दफ़न हैं, तुम हममें जिन्दा हो।

केरल : बेमिसाल उपलब्धियों का शानदार रिकार्ड

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विपरीत, केरल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार जन-समर्थक नीतियां लागू कर रही है। जहां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में व्यवसायीकरणऔर कट्टरपंथ थोप रही हैं, वहीं केरल में वाम मोर्चा सरकार के काम श्रमिकों के कल्याण पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने राज्य के विकास को अस्थिर करने और केरल के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय फंड्स को रोक कर रखा है, जब कि कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भी कटौती की गई है। मोदी सरकार बजट का अभाव पैदा करने और केरल सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है।

केरल में वाम मोर्चा सरकार जनता, श्रमिक वर्ग और मेहनतकश जनता की सरकार है। यह सरकार सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए केरल सरकार की रक्षा की जानी चाहिए। एआईएडब्ल्यूयू, सीआईटीयू, और एआईकेएस के तत्वावधान पर 11 दिसंबर को पूरे देश में केरल एकजुटता दिवस का आयोजन कर केरल के प्रति केंद्र सरकार के नकारात्मक रुख को उजागर किया जाना चाहिए। यह आयोजन केरल के लोगों को स्पष्ट संदेश देगा कि देश का श्रमिक वर्ग और प्रगतिशील वर्ग राज्य के साथ खड़े हैं और अपना अटूट समर्थन प्रदान कर हैं।

राज्य स्तर पर पहली बार, केरल सरकार ने एक व्यापक कृषि श्रमिक कानून बनाया है जो श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों और अन्य लोगों को लाभ पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त, ईएमएस सरकार ने देश में पहली बार भूमि सुधार लागू किया था और गरीबों को जमीन वितरित की थी। 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को खेती योग्य भूमि उपलब्ध करायी गयी है। 'नवा केरल' पहल का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को खेती योग्य भूमि उपलब्ध कराना है। पिछली एलडीएफ सरकारों ने भी आबादी के एक बड़े हिस्से को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 'लाइफ मिशन' कार्यक्रम के तहत 5 लाख परिवारों की पहचान कर गरीबों के लिए 4.5 लाख मकान बनाये गये हैं जिनका गृह प्रवेश का कार्य एक ही दिन में पूरा किया गया।

हर गरीब परिवार को पेंशन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, कृषि श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत, अब 60 लाख परिवारों को हर महीने वैधानिक पेंशन मिलती है। अन्य राज्यों के विपरीत, जहां पेंशन सरकारों के विवेक के अधीन है, केरल ने एक वैधानिक पेंशन प्रणाली स्थापित की है। वाम मोर्चा सरकार की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता इस तथ्य से और भी प्रदर्शित होती है कि खेत मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों को प्रतिदिन 800 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक की दैनिक मजदूरी दी जाती है।

सरकार ने ग्रामीण गरीबों की पहचान करने और उन्हें स्थानीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्रमिक बैंकों की भी स्थापना की। सरकार के काम से प्रोत्साहित हो कर, कृषि श्रमिक संघों ने इस पहल का समर्थन करने के लिए स्वयंसेवी प्रणाली स्थापित की है। कृषि मौसम के दौरान किसानों पर बोझ डाले बिना खेत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। जब फसल से मुनाफा हो जाता है, तब किसान, पंचायतों को भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि श्रमिकों के समर्थन के लिए एक पेंशन बोर्ड भी बनाया गया है।

देश के कई हिस्सों में खेत मजदूरों और ग्रामीण गरीबों द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक छुआछूत और भेदभाव के विपरीत, केरल अपनी प्रगति के लिए खड़ा है।

केरल में दलितों ने मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त होकर इतिहास रचा है, और यहां तक कि उन्हें बंदोबस्ती विभाग का मंत्री भी बनाया गया है। दलितों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। जहां भाजपा शासित राज्यों में दलितों और महिलाओं पर हमले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, वहीं केरल ने सभी जातियों के लोगों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, केरल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र, जो ऐसे अपराधों की सूची में शीर्ष पर हैं, जैसे राज्यों की तुलना में दलितों और महिलाओं पर हमलों की दर काफी कम है।

केरल में खेती का क्षेत्र 50 लाख एकड़ से कम है, जिस पर मुख्य रूप से रबर, मसाले, नारियल और काजू जैसे फसलें उगाई है। चावल, दाल, दूध और सब्जियां जैसी 50 प्रतिशत से अधिक आवश्यक वस्तुएं पड़ोसी राज्यों से आयात की जाती हैं, जिसकी लागत हजारों करोड़ रुपये होती है। इसके अतिरिक्त, केरल की 85 प्रतिशत आबादी को राशन की दुकानों के माध्यम से 10-12 प्रकार के सामान वितरित किए जाते हैं। केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के लिए एक मॉडल बन गई है। नीति आयोग के अनुसार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत, गुजरात में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक (17 प्रतिशत) है, जबकि केरल 0.7 प्रतिशत के साथ काफी निचले स्थान पर है।

केरल सरकार धान और सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती है। किसानों को केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल धान पर 600 रुपये का बोनस मिलता है। सरकार घरेलू सब्जी की खेती को भी प्रोत्साहित करती है और कृषि श्रमिकों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। धान की खेती को बढ़ावा देने के पक्ष में रबर की खेती कम करने की एक सोची समझी नीति चल रही है।

केरल में वाम मोर्चा सरकारों ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानव विकास को प्राथमिकता दी है। विजयन सरकार ने 'विद्याकिरणमयी' परियोजना शुरू की है, जिसमें 45,000 कक्षाओं को उच्च तकनीक वाले कमरों में बदलने के लिए 4,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट शिक्षा के साथ प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। जहाँ एक तरफ पूरे देश में सरकारी स्कूलों में दाखिला घट रहा है, केरल सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या बढ़ रही है। गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है जो उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देती है।

केरल स्वास्थ्य सेवा में भी अग्रणी है। राज्य प्राथमिक अस्पतालों से लेकर सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों तक एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी सुविधाएं गांव और कस्बे के स्तर पर उपलब्ध हों। सभी गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है और 96 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में होते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान केरल की चिकित्सा देखभाल को अमेरिका से प्रशंसा भी मिली थी। विजयन सरकार ने 'करुणमयसंपूर्णआरोग्ययोजना' शुरू की, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त सुपर-स्पेशियलिटी उपचार प्रदान किया जाता है और 5 लाख रुपये तक का खर्च भी उठाया जाता है।

महिलाओं के लिए, 'कुदुम्बश्री' योजना शुरू की गई, जो प्रत्येक गांव को 25,000 रुपये आवंटित करती है। गांवों के कई विकास परियोजनाएं कुदुम्बश्री महिलाओं द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, जिससे एक बड़ी बचत होती है, जो महिला सशक्तिकरण के मामले में देश के लिए एक मिसाल है। प्रति 1,000 जन्म पर 1,084 लड़कियों और 943 लड़कों का लिंग अनुपात केरल में महिलाओं की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता और बढ़ रही है।

केरल सरकार न केवल राज्य के लोगों बल्कि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इन प्रवासी श्रमिकों को केवल श्रमिक के बजाय 'अतिथि श्रमिक' कहा जाता है। जब तक वे केरल में रहते हैं, उन्हें आवास, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह समर्थन, रोजगार ढूंढ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए केरल को पसंदीदा स्थान बनाता है।

केरल में एलडीएफ सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए 'नवा केरल' पहल शुरू की है कि विकास न्यायसंगत हो और सभी नागरिकों के कल्याणकारी हो। 83,000 करोड़ रुपये की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण के मामलों में 40 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है। सरकार अपनी नौकरी खोने वाले श्रमिकों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। राज्य स्तर पर एक लाख करोड़ रुपये आवंटित कर, केरल सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, जो सहकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुंचा रहा है। गुजरात जैसे राज्यों में जहां 10,000 से कम सरकारी नौकरियां सृजित हुईं, वहीँ केरल की विजयन सरकार ने 3 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। केरल ने सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के आरक्षण को जारी रखा है।

केरल की आधी से अधिक आबादी के मुसलमान और ईसाइ, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, होने के बावजूद,केरल सांप्रदायिक सद्भाव का एक मॉडल बना हुआ है। राज्य अपने संपूर्ण लोगों के कल्याण, विकास और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए समर्पित है।

हालाँकि, केरल के कहीं अधिक समावेशी दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए, गुजरात के कॉर्पोरेट मॉडल को राष्ट्रीय मानक के रूप में बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी और आरएसएस द्वारा कठोर प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को उकसाकर और इस मजबूत राज्य सरकार की फंडिंग रोककर केरल को कमजोर करने का प्रयास कर रही है वहीं केरल सरकार विरोध करने के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए, लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की अनुमति देती है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें और अन्य दल अक्सर असहमति को सख्ती से दबा देते हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में, केरल ने केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण कार्यों के विरोध में दिल्ली में धरना भी दिया था।

केरल सरकार अपने लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है और इस सरकार की सुरक्षा और समर्थन करना देश भर के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। मोदी जी के नेतृत्व वाले गुजरात मॉडल और वामपंथी दलों के नेतृत्व वाले केरल मॉडल के बीच चल रहे संघर्ष में, यह महत्वपूर्ण है कि सभी मेहनतकश लोग केरल के साथ खड़े हों। केरल के लोगों ने जरूरत के समय लगातार उदारता दिखाई है। उन्होंने तेलंगाना में मुदिगोंडा नरसंहार के पीड़ितों की सहायता के लिए 60 लाख रुपये का दान दिया और वायनाड में आपदा का जवाब सैकड़ों करोड़ रुपये के दान से दिया। हमें केंद्र सरकार के भेदभाव के सामने केरल के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए।

वे सीताराम, जिन्हें मैं जानता था..

मुरलीधरन

कॉमरेड सीताराम येचुरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उनके जीवन, उनकी राजनीतिक यात्रा, एक सांसद के रूप में उनके काम, मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांत की व्याख्या करने और उसे भारतीय परिस्थितियों में लागू करने तथा पार्टी की वैचारिक स्थिति को आकार देने में उनके योगदान, तथा वैचारिक रूप से भिन्न और परस्पर विरोधी दलों को इण्डिया ब्लॉक की छतरी के नीचे लाने में उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका के बारे में। इसलिए मैं इनमें से किसी के बारे में बात नहीं करूंगा और खुद को कुछ व्यक्तिगत किस्सों और निश्चित रूप से कुछ सामान्य बातों तक सीमित रखूंगा, जिनके बारे में कम ही बात की गई है।

जब यह लेख प्रकाशित होगा, तब तक उन्हें हमें छोड़े हुए दो महीने से अधिक हो चुके होंगे। हालांकि शुरुआती सदमा और पीड़ा काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी सामंजस्य बिठाना और नुकसान से उबरना मुश्किल है, खासकर, यदि आपका रिश्ता चार दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है, जहां आपको विभिन्न क्षमताओं में उनके अधीन और साथ काम करने का सौभाग्य मिला है।

दिल्ली के विशाल बोट क्लब में मैंने पहली बार व्यक्तिगत रूप से सीताराम को देखा था। मैं उन लाखों लोगों में से एक था, जिन्होंने 15 सितंबर, 1981 को 'सभी के लिए शिक्षा और रोजगार' के केंद्रीय नारे पर दिल्ली में एक रैली के लिए एसएफआई और डीवाईएफआई के संयुक्त आह्वान पर हिस्सेदारी की थी। राजसी दिल्ली, जहां मैं पहली बार गया था, की भव्यता और शान के अलावा मैं सीताराम की विचारों की उस स्पष्टता और सरलता से आश्चर्यचकित था, जिसके माध्यम से वे चीजों को व्यक्त करते थे। मैं उनसे फिर से मिला, और इस बार करीब से कुछ महीनों बाद बॉम्बे (अब मुंबई) में एसएफआई के चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन में, जिसमें मैंने गुजरात के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

हालांकि, दिल्ली शिफ्ट होने (जिसके लिए वे मददगार थे) से पहले और बाद में मेरी उनसे जितनी भी मुलाकातें और बातचीत हुई हैं, उनमें से एक आज भी कई कारणों से मेरी यादों में ताजा है।

यह मुलाकात 1986-87 के बीच में कभी हुआ था। गुजरात में तत्कालीन एसएफआई इकाई में कुछ संगठनात्मक मुद्दे थे और तत्कालीन राज्य अध्यक्ष अरुण मेहता और (महासचिव के रूप में कार्यरत) मुझे दिल्ली बुलाया गया था। जब हम 22, विट्ठलभाई पटेल हाउस में स्थित एसएफआई कार्यालय पहुंचे, तो हमने सीताराम सहित कई नेताओं को वहां बैठे पाया। हिंदी में बातचीत करते हुए, उनमें से किसी ने हमारी यात्रा का उद्देश्य पूछा। मैंने बेपरवाही से प्रसिद्ध कल्याण सुमनपुरी/मोहम्मद रफ़ी गीत का हवाला देते हुए जवाब दिया, 'तुमने पुकारा और हम चले आए'। सीताराम की ओर से तुरंत उसी तरह से, अगर ज्यादा नहीं तो सहज लेकिन मजाकिया अंदाज में पलट जवाब आया 'जान हथेली पर ले आए'। हम सभी हंसते हुए लोटपोट हो गए। लेकिन संगीत, फिल्मों और निश्चित रूप से सिगरेट (जिसे मैंने बाद में छोड़ दिया और जिसकी वजह से आखिरकार उनकी जान चली गई) के लिए समान प्रेम, विचारधारा के अलावा, कुछ ऐसा था जिसने तुरंत एक बंधन बना दिया।

जितनी भी श्रद्धांजलियां मेरे समक्ष आई, उनमें से जो मुझे उनके व्यक्तित्व को अधिक प्रतिबिंबित करती लगी, वह थी प्रो. प्रभात पटनायक की श्रद्धांजलि। वह इस बात पर गहराई से प्रकाश डालती है कि कैसे जीवन के प्रति उनका नजरिया और उनका राजनीतिक कार्य मिश्रित होकर उन्हें वो सीताराम बनाता था, जो हममें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट था।

बसंत कुंज के उनके फ्लैट में शायित उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरों में पृष्ठभूमि में अंदाज फिल्म का एक फ्रेम लगा हुआ पोस्टर दिखाई दे रहा था। यह महबूब खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी एक फिल्म थी, जिसमें ऊपरी बाएं कोने में हथौड़ा और हंसिया का लोगो उभरा हुआ था। सिनेमा के उस युग के बारे में विचार करते हुए, सीताराम यह अनुमान लगाते हैं कि कैसे उस समय, विशेष रूप से स्वतंत्रता के तुरंत बाद के दौर, के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हिंदुस्तान टाइम्स में अपने नियमित कॉलम 'लेफ्ट हैंड ड्राइव' में वह सुजाता जैसी फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो छुआ-छूत के मुद्दे से निपटती हैं; दो बीघा जमीन जो भूमि सुधारों के सवाल को छूती है..., आदि। आगे बढ़ते हुए, वे प्रगतिशील लेखक संघ के इतिहास और मुंशी प्रेमचंद, फैज अहमद फैज, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी आदि जैसे लेखकों और कवियों पर इसके प्रभाव का पता लगाते हैं। इसी तरह, वे भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) के गठन के बारे में भी बात करते हैं जिसने पृथ्वीराज कपूर, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त, केए अब्बास, सलिल चौधरी आदि जैसे दिग्गजों को जन्म दिया। सीताराम को 'बॉलीवुड' शब्द से नफरत थी। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम के हॉलीवुड की नकल है। वह इसे हिंदी फिल्म कहना पसंद करते थे।

सीताराम पुराने गीतों के भी दीवाने थे और जैसा कि प्रो. पटनायक सही ही बताते हैं, उन्हें 'मदन मोहन किस्म' के गीतों का गहरा शौक था। हमारी कई बातचीत में से एक के दौरान सीताराम ने जेएनयू में बिताई गई उन रातों को याद किया, जब वे कैफी आज़मी और भूपेन हजारिका को सुनने में डूबे रहते थे। संगीत के प्रति उनका लगाव संकुचित नहीं था। उन्हें कर्नाटकी और हिंदुस्तानी दोनों ही पसंद थीं। इसके अलावा चाहे वह बीटल्स हो या माइकल जैक्सन। सीताराम कहते हैं कि 'जैक्सन एक गतिशील पीढ़ी की भावनाओं का प्रतीक थे। जब 1980 के दशक के आखिर में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई गाना देखा है, तो मैं दंग रह गया। मेरे तो सोच थी कि कोई भी गाना सिर्फ सुन सकता है। जैक्सन ने किसी और से बढ़कर पीढ़ियों को सिर्फ दृश्यात्मक रूप से नहीं बल्कि आकार दिया। संगीत के आनंद को देखना और उसका अनुभव करना ही सबसे बड़ी बात है'। बीथोवन के बारे में वे लिखते हैं, 'हमें अभी भी बीथोवन की 9वीं सिम्फनी से जूझना है। उन्होंने मानवीय आवाज का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें लगा कि वाद्यों की आवाज की रेंज अपर्याप्त थी। इसका अधिकांश हिस्सा बीथोवन ने तब रचा था जब वे पूरी तरह बहरे हो गए थे। उन्होंने सिम्फनी का प्रीमियर आयोजित किया और एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, इसके अंत में, पूरे दर्शकों ने पांच बार खड़े होकर तालियाँ बजाकर उनका अभिनंदन किया, हवा में रूमाल, टोपियाँ फेंकी गयी और हाथ उठाए गए, ताकि बीथोवन,जो तालियाँ नहीं सुन पा रहे थे, कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट तो देख सकें'।

सीताराम हमेशा कार में बैठते ही एफएम स्टेशन चालू कर देते थे और कुछ सदाबहार हिंदी गाने सुनते थे। उनके ड्राइवर राकेश कहते थे कि वे बटन और प्रीसेट स्टेशनों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करते, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें डाँट पड़ जाए।

28 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उनकी स्मृति के अवसर पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी के लिए, उनके जाने के कुछ दिनों बाद भी उनके पत्नी सीमा चिश्ती, जो तब भी दुःख में थी, द्वारा उनके निवास पर रखे गए ढेरों फोटोग्राफों को देखते हुए, उनकी बेटी अखिला की नजर एक फोटो पर पड़ी जो प्रदर्शनी का हिस्सा बन गई।

यह फोटो सीताराम नामक दस वर्षीय बालक की थी जिसके हाथ में टेनिस रैकेट था। वर्षों बाद, जब हम विट्ठलभाई पटेल हाउस के कोर्ट में बैडमिंटन खेला करते थे, तो वे कुछ ऐसे (टेनिस) स्ट्रोक खेला करता था, जैसा कि जॉन ब्रिटास ने कहीं और याद किया। खेलों के प्रति उनका उत्साह केवल इन दो खेलों तक ही सीमित नहीं था। हालांकि वह अन्य खेलों में उतने उत्कृष्ट नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके प्रति उनका लगाव कम नहीं था। एक उत्साही क्रिकेट प्रशंसक के रूप में, वे तथाकथित सज्जनों के खेल - क्रिकेट के गिरते मानकों के बारे में चिंतित थे। अपमानजनक भाषा का प्रयोग, व्यावसायीकरण और अंत में आईपीएल की तरह खिलाड़ियों की नीलामी ने उन्हें काफी परेशान किया।

सीताराम कई भारतीय भाषाओं में पारंगत थे। 2010 में विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'मैं यहां तमिलनाडु में पैदा हुआ हूं, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, मैं हिंदी भाषी दिल्ली में बसा हूं, संसद में पश्चिम बंगाल के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और यहां दुनिया भर से आए तमिल भाषी लोगों की शानदार सभा को संबोधित कर रहा हूं। यही भारत है।'

वे एक बेहतरीन पत्रकार थे। एसएफआई के जर्नल स्टूडेंट स्ट्रगल के संपादक के रूप में उन्होंने न केवल चमकदार रंगीन कवर पेश किए, बल्कि सामग्री और प्रदर्शन की गुणवत्ता में भी काफी वृद्धि की। इसके पाठकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। मुझे उनके द्वारा उस समय निकाले गए दो विशेष अंक याद हैं। एक 1983 में कार्ल मार्क्स की जन्म शताब्दी पर था और दूसरा असम में विदेशी विरोधी आंदोलन पर केंद्रित था। पीपुल्स डेमोक्रेसी के संपादक के रूप में उन्होंने पार्टी के साप्ताहिक में कई बदलाव किए थे। मार्क्सिस्ट के संपादक के रूप में, जो वह अपनी मृत्यु के समय तक थे, उन्होंने प्रत्येक अंक को एक विशिष्ट विषय को समर्पित करने का प्रयास किया। उन्होंने जो अंतिम खंड संपादित किया वह फिलिस्तीन पर था, एक ऐसा मुद्दा जो उनके दिल के करीब था।

मैंने 1988 में पार्टी के त्रिवेंद्रम (13वें) कांग्रेस की पूर्व संध्या पर 14 अशोक रोड पर पार्टी मुख्यालय में काम करना शुरू किया। तब अपना कोई भवन न होने के कारण पार्टी को अपने सांसदों को आवंटित आवास पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय यह बंगला दार्जिलिंग से लंबे समय से सांसद रहे कॉम आनंद पाठक को आवंटित था। एक तरफ कॉमरेड ईएमएस नम्बूदीरीपाद के लिए एक कमरा था और दूसरी तरफ कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के लिए एक कमरा था। इन दो दिग्गजों के बीच में कॉमरेड प्रकाश करात और कॉमरेड सीताराम येचुरी थे। कॉमरेड एम बासवपुन्नईया पीछे के एक हिस्से में रहते थे। कॉमरेड बी टी रनदिवे का कार्यालय उस एनेक्सी में स्थित था जिसमें पीपुल्स डेमोक्रेसी का कार्यालय था। इन चार दिग्गजों ने, जैसा कि हम में से कुछ लोग कहते थे, 'चार का गिरोह' बनाया, वह स्तंभ जिन्होंने उस समय एक मजबूत केंद्र की नींव रखी।

सीताराम के पास सबसे छोटा कमरा था - एक ऐसा कमरा जिसमें मुश्किल से एक मेज और तीन कुर्सियाँ फिट हो सकती थीं। इस छोटे से कमरे में बैठकर, एक के बाद एक सिगरेट पीते हुए, कभी-कभी धुएँ के छल्ले उड़ाते हुए, सीताराम ने पार्टी की स्थिति को तैयार करने में अपना सबसे पहला योगदान दिया, जो कि 'कुछ वैचारिक मुद्दों' पर प्रस्ताव के रूप में था, एक दस्तावेज जिसे 1992 में सीपीआई (एम) की मद्रास (14वीं) कांग्रेस में पेश करने का काम उन्हें सौंपा गया था।

उन दिनों कार्यालय में कई धूम्रपान करने वाले थे - उनमें से 13वीं कांग्रेस में चुने गए केंद्रीय सचिवालय के सभी सदस्य (फिर उनके सेवन में भिन्नता हो सकती है) - एस रामचंद्रन पिल्लई, प्रकाश करात, सुनील मोइत्रा, पी रामचंद्रन, और निश्चित रूप से सीताराम -इसके अलावा कार्यालय में कुछ अन्य लोग। कॉमरेड सीताराम को छोड़कर हममें से अधिकांश ने धीरे-धीरे धूम्रपान छोड़ दिया।

अंत में, खाद्य वस्तुओं के प्रति सीताराम के उत्साही प्रेम के बिना उनके बारे में बात करना अनुचित होगा। जैसा कि उनके कई दोस्त और सहकर्मी बताते हैं, वे एक बार में कई तरह के व्यंजन खा

शेष पेज 15 पर

महिला अधिकारों की लड़ाई और बाबा साहब अम्बेडकर

संध्या शैली

हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक डा. बाबासाहेब अम्बेडकर की बडी विशेषता को पीछे कर उन्हें केवल दलितों के नेता के तौर पर स्थापित करना वर्तमान सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था की एक बड़ी साजिश थी।

बाबासाहेब की राजनैतिक और सामाजिक यात्रा की तुलना केवल महात्मा गांधी से की जा सकती है जिन्होंने राजनैतिक प्रश्नों के साथ साथ सामाजिक प्रश्नों को भी अपने लेखों, भाषणों, पुस्तकों में किया। भगतसिंह जरूर अपनी विचारधारा के बल पर उनके कद से प्रतियोगिता कर सकते थे लेकिन 23 साल की उम्र में हो गयी उनकी शहादत ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया।

बाबासाहेब देश के सामाजिक ताने बाने को समझने वाले और उत्पीड़ितों की मुक्ति के लिये संघर्ष करने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। तभी भारत की जनता ने यदि गांधी को महात्मा कहा तो अंबेडकर को महामानव।

उनके द्वारा दिया गया नारा उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व और लक्ष्य को दिखाता है - शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। वर्गीय और जातीय आधारों पर बंटे समाज में शोषितों को जगाने वाला और अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करने के लिये प्रेरित करने वाला इससे बड़ा नारा देश में नहीं है। शोषित कोई भी हो सकता है फिर वह सामाजिक रूप से दलित और अस्पृश्य हो,आर्थिक रूप से दलित मजदूर हो या फिर दोनों ही रूपों में दलित स्थिति को प्राप्त महिला हो। भारतीय समाज में उपस्थित इन तीनों ही प्रकार के शोषितों के लिये उन्होंने अपनी हर हैसियत में न केवल संघर्ष किया बल्कि उन्हें अधिकार भी दिये।

1942 से 1946 के बीच वाइसराय कौंसिल के सदस्य रहने के दौरान उन्होंने न केवल हिंदुस्तान के श्रमिकों के लिये सबसे पहले 8 घंटे काम का कानून बनवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। बल्कि महिला श्रमिकों के हितों के लिये भी कई कानून बनाये जो बाद में आजादी के बाद बने श्रमिकों के लिये बनाये गये कानूनों के लिये आधार बने। महिलाओं के लिये समान काम के लिये समान वेतन का कानून इस देश में बाबा साहेब की देन है। जो अमरीकी महिलाओ को आज भी प्राप्त नहीं है।

लेकिन उनका सबसे अधिक योगदान इस देश की महिलाओं के अधिकारों के लिये उनका संघर्ष था। भारत के इस पहले कानून मंत्री ने महिलाओं के हकों के प्रति अपने समर्पण की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जब लोक सभा में हिंदू कोड बिल के खिलाफ तमाम जनसंघी और तत्कालीन राष्ट्रपति सहित तथाकथित प्रगतिशील कांग्रेस के नेता भी खडे हो गये। यहां यह बात ध्यान देने की है कि इस बिल के सदन में पेश करने के पूर्व संविधान सभा ने देश में नागरिकों के बीच धर्म, जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की संविधान की मूल प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद महिलाओं के अधिकारों को देने वाले इस विधेयक का कड़ा विरोध और इसके खिलाफ जनसंघ के द्वारा कमेटी का गठन भी संघ के द्वारा कर लिया गया था। इस पर कड़ा आक्षेप लेते हुये डा. अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उनके इस बिल के सभी पक्षों को नेहरू सरकार ने अलग अलग कानून बनाकर इसे लागू कर दिया। इसमें उन्हें 10 साल लग गए।

अम्बेडकर के प्रति इस देश की महिलाओं को इसलिये भी ऋणी रहना चाहिये कि उनकी अगुआई में आजादी के बाद महिलाओं को कानूनन कई अधिकार दिय, इनमें सबसे प्रमुख था वोट देने का अधिकार। दुनियां भर में सोवियत संघ और चीन के अलावा उस वक्त बहुत कम देश ऐसे थे जिनमें आजादी के साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।

अंबेडकर का दृढ मानना था कि इस देश को एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न देश बनाने में मनुवाद सबसे बडा अडंगा है। मनुवादी परंपराये संघर्ष से भी खत्म होंगी लेकिन जहां पर भी मौका मिले वहां पर शोषितों को कानूनन अधिकार देने से भी ये परंपरायें कमजोर होंगी। उनका यह भी मानना था कि इन परंपाराओं की सबसे बड़ी वाहक महिलायें हैं जो खुद इसकी बेड़ियों भी जकड़ी हुयी हैं। इसलिये वे महिलाओं की शिक्षा के सबसे बडे झंडाबरदार थे। कोलंबिया युनिवर्सिटी में उनके एक शोध पत्र का आधार भी यही था।

डा अंबेडकर ने केवल अपने बोलने और लिखने में ही महिलाओं के हकों की बात नहीं की बल्कि उनके हर आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की। 20 जुलाई 1940 को नागपुर में अखिल भारतीय शोषित पीड़ित महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुये उन्होंने महिलाओं के संगठन के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनके नेतृत्व में हुये कई आंदोलनों में न केवल दलित ओर आदिवासी महिलाओं ने बल्कि सवर्ण महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की।

डा.अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि आजादी के बाद भारतीय समाज जाति आधारित गैरबराबरी वाला समाज नहीं होना चाहिये। इसलिये उन्होंने शिक्षा, अंर्तजातीय विवाह और सामूहिक भोज के तरीके अपनाने पर जोर दिया जिससे पितृसत्ता और मनुवादी परंपराओं की जकड़न टूटती। महाड सत्याग्रह के बाद उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था जिसमें करीब 50 महिलाओं ने भाग लिया था।

डा.अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को सदन में प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि आज के बाद से हम एक अंर्तविरोधों से भरे समाज में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हमने राजनैतिक रूप से सभी नागरिकों को समानता दी है लेकिन आज भी हमारा समाज, लैंगिक,सामाजिक, धार्मिक रूप से भयानक गैरबराबरियों पर टिका हुआ है। ये गैरबराबरियां जब तक जिंदा रहेंगी तब तक इय राजनैतिक बराबरी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा रहेगा। इसलिये देश के संविधान की मूल आत्मा यानि देश के हर नागरिक के समान अधिकार की भावना की रक्षा करना है तो जितनी जल्दी इन गैरबराबरियों से छुटकारा मिले उतना अच्छा होगा।

डा.अंबेडकर का यह कथन आज भी उतना ही सच है जितना 1950 में था।

(स्त्रोत-लोकजतन फाइल)

डा.अम्बेडकर स्मरण दिवस पर जमस ने किये कार्यक्रम

नीना शर्मा

भोपाल। डा.अम्बेडकर के स्मरण दिवस पर भोपाल में आचार्य नरेन्द्र देव नगर में कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बोलते हुये वक्ताओं ने कहा कि अम्बेडकर का योगदान केवल शोषित, दलित तबकों को बराबरी पर लाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर नागरिक के मानवाधिकार की रक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किये। वे समाज में महिलाओं के शोषण के खिलाफ भी मुखर होकर आगे आये।

कानून मंत्री रहते हुये हिंदू कोड बिल लेकर आये जिसमें मर्जी से शादी करने तलाक लेने, सम्पति में अधिकार, उतराधिकार के अधिकार की बात थी, कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठनो ने इसका इतना विरोध किया था कि अम्बेडकर ने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में नेहरू जी ने पहल कर इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनवाये ।डा.अम्बेडकर महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से मजबूती के पक्षधर थे।

जमस की स्थानीय इकाई की उपाध्यक्ष नूर बी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को राज्य अध्यक्ष नीना शर्मा तथा जिला सह सचिव किरण राजपूत ने संबोधित किया।

किरण ने कहा कि धार्मिक और जातीय भेदभाव आज और तेजी से बढ़ रहे हैं महिलाओं का शोषण भी बढ़ रहा है। जो अधिकार संघर्षो के जरिये हासिल किये थे, उन्हें निष्क्रिय किया जा रहा है। इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाये संविधान को बचाने की जरूरत है।

सीहोर के दशहरा बाग में डा.अम्बेडकर जयंती की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक संतोष प्रजापति ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर कर ने औरतों को दिलाये आज उन्हें खत्म किया जा रहा है, उनके नारे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के नारे को समझ कर उसे अमल में लाकर औरतें समाज में अपना वजूद बना सकती है।

केरल ने करके दिखाया कि मुमकिन है विकल्प

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वैश्वीकरण-समर्थक कॉर्पोरेट नीति के विपरीत केरल में एलडीएफ सरकार वैकल्पिक नीतियां लागू कर रही है।

1. कृषि क्षेत्र

केंद्र - कृषि क्षेत्र का व्यवसायीकरण, किसानों को मिलने वाली सहायता में कटौती। न्यूनतम समर्थन मूल्य के पूर्णत: विरुद्ध। फसल की खरीद में गिरावट। किसान विरोधी कानून ला रहे हैं।

केरल - कृषि विकास दर 2 फीसदी से बढ़कर 4.64 फीसदी हुई।धान की खेती, जो केवल 1.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर होती थी, बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर पर होती है। सब्जियों की खेती, जो 60,000 हेक्टेयर ज़मीन तक सीमित थी, अब 1.20 लाख हेक्टेयर जमीन तक विस्तारित हो गई है। कृषि मूल्यवर्धन के उद्देश्य से पार्कों (चावल, कॉफी, मसाले, भोजन, रबर,नारियल) का संचालन शुरू किया गया है। सब्जियों के लिए देश में पहली बार समर्थन मूल्य लागू किया गया है। देश में धान का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य केरल में दिया जाता है। सरकार नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किसानों से धान भी खरीदती है। दूध का उत्पादन काफी बढ़ गया है। किसानों के लिए 'किसान कल्याणफंड' को भी लागू किया गया है। एक किसान को रुपए 5000 पेंशन भी दी जाती है। 'कृषि ऋण राहत आयोग' का गठन किया गया है जो किसानों को उनके कर्ज से राहत दिलाने के लिए काम कर रहा है। इससे हजारों किसानों को राहत मिली है। केरल एकमात्र राज्य है जहां कोई किसान आत्महत्या नहीं करता।

2. उद्योग

केंद्र - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को बेचाजा रहा है। पारंपरिक उद्योगों को सहायता में कटौती की जा रही है।

केरल - औद्योगिक विकास 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम लाभदायक हो गए हैं। यूडीएफ शासन के दौरान, केवल 8 उद्यम लाभदायक थे। कई अन्य बंद हो गए थे और कई बंद होने की प्रक्रिया में थे। अब 41 उद्यम फायदे में हैं। वेल्लोर न्यूज प्रिंट फ़ैक्टरी, जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर बिक्री के लिए रख दिया था।

राज्य उद्योग विभाग द्वारा खोला और संचालित किया गया। भारत के बड़े समाचार पत्र कम्पनियाँ यहीं से कागज खरीदती हैं। यूडीएफ शासन के दौरान, सभी उद्यम घाटे में थे। अब सभी 384.68 करोड़ रुपये का मुनाफे में हैं। 1,40,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शुरू किये गये हैं। पांच साल में 92,000 करोड़ रुपाए के निवेश केरल में आये हैं। 1,39,840 स्टार्टअप शुरू किये गये हैं। इसके जरिए 92,000 करोड़ रुपये रुपये का निवेश हुआ और 3 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं। जब एलडीएफ सत्ता में आया, तो यह उद्योग-अनुकूल सूची में 23वें स्थान पर था। अब यह पहले स्थान पर पहुंच गया है।

3. सामाजिक पेंशन

केंद्र - वृद्धा-विधवा-विकलांगों को पेंशन के रूप में 200 से 500 रुपए ही दिए जाते हैं जिसमे पिछले 12 साल से एक रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। यहां तक कि इस अल्प हिस्से को राज्यों को नहीं दिया जाता।

केरल - 2016 में 34 लाख लोगों को पेंशन मिली जिसके अंतर्गत प्रति माह 600 रुपये दिये जाते थे। अब यह 60 लाख लोगों को दी जाती है जिनको प्रति माह 1600 रुपये दिये जाते हैं। यूडीएफ शासन के दौरान 2011 से 2016 तक पेंशन पर कुल खर्च 9011 करोड़ रुपये था। एलडीएफ के 8 वर्षों के दौरान यह खर्च 61,000 करोड़ रुपये पहुँच गया है। हर महीने पेंशन को लोगों के घरों तक पहुंचा दी जाती है।

4. एससी/एसटी कल्याण

केंद्र - जनसंख्या के अनुपात में फंड का आवंटन नहीं किया जात है। इस तब के के साथ घोर भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा है।

केरल - आबादी से ज्यादा फंड आवंटित किया गया है। पिछले वित्तीयवर्ष में, अकेले अनुसूचित जाति वर्ग पर 2,980 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अनुसूचित जाति की आवासीय समस्या को हल करने के लिए 770 करोड़ रुपये खर्च किये गये जिस से 56,994 परिवार लाभान्वित हुए जिन को 3,937 एकड़ भूमि वितरित की गई अनुसूचित जनजाति वन अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। 41अनुसूचित जनजाति बस्तियां जहां बिजली नहीं थी, को बिजली उपलब्ध करायी गयी है। 1,099 अनुसूचित जनजाति बस्तियों को नि:शुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। नि:शुल्क प्रदान किया गया। 'कॉलोनी' शब्द को राज्य की शासन प्रणाली से हटा दिया गया है।

5. सार्वजनिक वितरण

केंद्र - सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाधित किया जा रहा है। खाद्य सब्सिडी में कटौती की जा रही है ।

केरल - सार्वजनिक वितरण को मजबूत करने के लिए धन आवंटित किया गया है। जब यूडीएफ सत्ता में थी, तब कुल रु. 5,242 करोड़ दिए गए। एलडीएफ सरकार ने अकेले पांच साल में 10,697 करोड़ रुपये दिये। प्राथमिकता श्रेणी के अलावा,राज्य अनुदान के साथ अन्य श्रेणियों को भी राशन आवंटन दिया जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत सभी पंचायतों में मावेली स्टोर बनाये जा रहे हैं और सहकारिता विभाग के अंतर्गत नीति स्टोर शुरू किये जा रहे हैं। एनएसओ के अनुसार, मूल्य मुद्रास्फीति की दर केरल में सबसे कम है।

6 आवास

केंद्र - आवास निर्माण सहायता योजना को कमजोर किया जा रहा है। केंद्रांश मात्र रु. 72,000 है।

केरल - गरीबों को घर मुहैया कराने के लिए 'लाइफ' योजना शुरू की गई है। प्रत्येक मकान के लिए 4 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। 410,000 घर पहले ही बन चुके हैं। 50,000 और घर पूरे किये जा रहे हैं। फ्लैट बनाए जा रहे हैं. और जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

7. स्वास्थ्य क्षेत्र

केंद्र - सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र से अपना हाथ खींच रही है।

केरल - वे सभी सरकारी अस्पताल जिन पर आम लोग भरोसा करते हैंमें सुधार हुआ है। सभी पंचायतों में पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गयी है। पूर्णकालिक चिकित्सक सेवा प्रदान की जाती है। सभी तालुक-जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं में विस्तार हुआ है जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। यूडीएफ शासन के दौरान इस क्षेत्र का बजट आवंटन 600 करोड़ था। एलडीएफ सरकार लगभग 2500 करोड़ प्रदान कर रही है।

8. शिक्षा

केंद्र - सरकार शिक्षा क्षेत्र में निवेश में कटौती कर रही है. उच्च शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण क्या जा रहा है तथा स्कूल बंद किये जा रहे हैं।

केरल - एलडीएफ के सत्ता में आने जिन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया था, सरकार ने उनका अधिग्रहण कर लिया है और उनके बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की इमारतें और प्रयोगशालाएँ जैसे बुनियादी ढाँचे में काफी हद तक विस्तार और सुधार किया गया है। कक्षाओं को स्मार्ट बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि की गई है। 8 साल में. 5000करोड़की बढ़ोतरी हुई है. 10 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में शामिल हुए हैं। केरल में उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत किया गया है। भारत के 15 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से 3 विश्वविद्यालय केरल में हैं। देश के शीर्ष 200 कॉलेजों में से 42 केरल में हैं। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में शुरू की गई है।

9 सरकारी नियुक्तियाँ

केंद्र - रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं।. करीब 10 लाख रिक्तियां अकेले केंद्रीय सेवा में है।

केरल - 8 साल में 2,27,800 नियुक्तियां की गयी हैं और अन्य विभागों को रिक्तियों की रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। सभी राज्यों में हुई कुल पीएससी नियुक्तियों का 60 प्रतिशत केरल में हुआ है।

10. अत्यधिक गरीबी उन्मूलन

2021 में नीति आयोग के मुताबिक भारत की 25 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे आयेगी। केरल भारत का सबसे कम गरीबी वाला राज्य है जिसकी मात्र 0.71 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। यह एक प्रतिशत से भी कम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि अत्यधिक गरीबी को राज्य से समाप्त किया जायेगा। इसको लेकर पिनाराई सरकार की दूसरी कैबिनेट की पहली बैठक में अहम फैसला लिया गया जिस के माध्यम से अति गरीबों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी की गई जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक चली जनभागीदारी गतिविधियाँ में केरल के 64,006 परिवार अत्यंत गरीब पाए गए। हालाँकि यह एक छोटी संख्या है, लेकिन वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहती है। राज्य में 64,006 परिवार बेहद गरीब हैं जिन में से 35 प्रतिशत परिवारों के पास आय का कोई साधन नहीं है और 24 प्रतिशत को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। 21 प्रतिशत खाद्य असुरक्षित हैं। 3 प्रतिशत कमजोर वर्ग, 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं तथा 2,737 परिवार तटीय निवासी हैं।सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है किकेरल में एक भीव्यक्ति अति गरीबन हो।केरला से अत्यधिक गरीबी दूर की जायेगी। केरल भारत का पहला अत्यधिक गरीबी उन्मूलन राज्यबनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

11. मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीयोजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9.94 करोड़ रोजगार दिवस सृजित किये गये। जिनका की औसत 67.7 कार्य दिवस है।

अनुसूचित जनजाति परिवार जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया हो को केरल राज्य सरकार ने 100 अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया। ट्राइबल प्लस के माध्यम से 16.32 लाख रोजगार दिवस सृजित किये गये हैं।

केरल में अय्यंगली शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है जो एक वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल मजदूरी करने के इच्छुक हों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।

केरल भारत का एकमात्र राज्य है जिसने शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इस परियोजना को राज्य के बजट के माध्यम से क्रियान्वयन किया गया। अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना माध्यम से 26.5 लाख रोजगार दिवस सृजित किये गये हैं।

केरल एकमात्र राज्य है जिसने गारंटी कार्यकर्ता के लिए कल्याण निधि शुरू की है। इसके साथ ही राज्य सरकार सालाना त्योहारों के दौरान सभी श्रमिकों को त्योहार भत्ताके रूप में 1000 रुपये भी देती है। इन सबके अलावा विकास के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, गेल पाइप लाइन का पूरा होना, विझिंजम बंदरगाह, इदामोन-कोच्चि पावर हाईवे, सरकारी इंटरनेट के-फोन आदि केरल के बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण सफलता।

सीरिया - 10 कारण जिनकी वजह से बशर अल-असद के सीरिया पतन हुआ

विजय प्रसाद

रविवार, 8 दिसंबर को सीरियाई सरकार और आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एच टी एस) और उसके सहयोगी गुटों के बीच एक सप्ताह से अधिक समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद, जिसने देश के प्रमुख शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और जिसके परिणामस्वरूप सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद सीरिया से भाग गए हैं। इस खबर की घोषणा रूसी विदेश मंत्रालय ने की, जिसमें यह भी बताया गया कि अपने इस्तीफे के साथ, अल-असद ने अपने प्रधानमंत्री को विपक्षी ताकतों को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की देखरेख के लिए राज्य के प्रभारी बने रहने का निर्देश दिया है।

यह घटनाक्रम गज़ा में इजरायल के नरसंहार के 14 महीने बाद और हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही सप्ताह बाद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मसलों के विशेषज्ञ विजय प्रसाद द्वारा अधिग्रहण और इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की गई है। उन्होंने इस घटना विकास के 10 कारण बताये जो इस प्रकार हैं ;

1. सीरियाई राज्य 2011 में शुरू हुए युद्ध और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा देश पर लगाए गए प्रतिबंधों से तबाह हो गया था। सीरियाई अरब सेना (आधिकारिक राज्य की सेना) प्रमुख लड़ाई के बाद कभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाई और हमा, होम्स और अलेप्पो के मुख्य शहरों को वापस लेने में असमर्थ रही थी।

2. सीरियाई सैन्य ठिकानों पर इजरायली बमबारी ने सीरियाई सशस्त्र बलों की रसद और आयुध क्षमताओं को कमजोर कर दिया था। ये हमले सीरियाई सशस्त्र बलों पर लगातार हो रहे थे और काफी भयावह थे।

3. लेबनान पर इजरायली आक्रमण और हिजबुल्लाह नेता सैय्यद हसन नसरल्लाह की हत्या ने लेबनान के दक्षिण में भी हिजबुल्लाह की ऑपरेशन की क्षमता को कमजोर कर दिया था, जिसके कारण हाल ही में इजरायल के साथ 'युद्धविराम' समझौता करना पड़ा। इससे यह पता चला कि हिजबुल्लाह सीरिया में फिर से प्रवेश करने की स्थिति में नहीं था, ताकि हमा से दमिश्क रोड (हाईवे एम5) पर किसी भी सशस्त्र घुसपैठ के खिलाफ सीरियाई सरकार का बचाव किया जा सके।

4. सीरिया में ईरानी आपूर्ति डिपो और सैन्य यूटिलिटी पर हमलों के साथ-साथ ईरान पर इजरायल के हमलों ने सीरियाई सरकार की रक्षा के लिए ईरानी सेना के किसी भी विस्तार को रोक दिया था। हिजबुल्लाह के कमजोर होने से क्षेत्र में ईरान की भूमिका भी कमजोर हुई है।

5. यूक्रेन में लगभग तीन वर्षों से चल रहे युद्ध ने निश्चित रूप से सीरिया को दमिश्क की सुरक्षा के लिए या लताकिया में रूसी नौसैनिक अड्डे के लिए आगे रूसी सहायता मांगने की क्षमता से वंचित कर दिया है।

6. इसलिए, सीरिया की सरकार के पास अब मजबूत विद्रोहियों के खिलाफ सहायता के लिए ईरानी और रूसी सैन्य सहयोगी नहीं थे।

7. 2017 में अल-कायदा के संगठनों से गठित हयात तहरीर अल-शाम ने तुर्की से लेकर उइगरों तक के विभिन्न सैन्य बलों को एक साथ ला दिया था - जिसमें बड़ी संख्या में अन्य अल-कायदा प्रभावित लड़ाके भी शामिल थे - और पिछले एक दशक में इदलिब में इसने अपनी सेना का निर्माण किया था। एचटीएस को तुर्की से सहायता और समर्थन मिला है, लेकिन गुप्त रूप से इज़रायल से भी मिला है (यह जानकारी मुझे तुर्की में एक उच्च पदस्थ खुफिया अधिकारी से मिली है)।

8. एचटीएस के नेतृत्व वाली नई सरकार सीरिया में कई सामाजिक अल्पसंख्यकों के बारे में क्या करेगी? एचटीएस के नेतृत्व वाली नई सरकार गोलान हाइट्स और इज़रायल के बारे में क्या करेगी? क्युनेत्रा में इज़रायली सैन्य घुसपैठ को एचटीएस की नई सरकार किस तरह से देखेगी, यह अभी देखना बाकी है?

9. यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देश में आईएसआईएस (दुइस्ड्स) के साथ-साथ उत्तर में कुर्द समूहों के नेतृत्व में और भी अशांति होगी; पहले से ही तुर्की समर्थित समूह मनबीज में कुर्द आयपीजी (पीपुल्स डिफेंस यूनिट्स) और पीकेएक (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) बलों के खिलाफ लड़ाई में हैं; अमेरिकी सेना पहले से ही पूर्वी सीरिया में है, जहां उनका कहना है कि वे आईएसआईएस के खिलाफ एक बफर के रूप में रहेंगे (और इसलिए तेल पर नियंत्रण बनाए रखेंगे); इज़रायल ने यह भी घोषणा की है कि उसने गोलान बफर ज़ोन पर कब्ज़ा कर लिया है। तुर्की और अमेरिका की सरकारों के बीच इस बात को लेकर तनाव रहेगा कि नई एचटीएस के नेतृत्व वाली सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

10. मुझे बहुत उम्मीद है कि अबू मोहम्मद अल-जोलानी द्वारा दिए गए इस बयान, कि प्रतिशोध नई संस्कृति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सच होगा। असली डर अल्पसंख्यक आबादी के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इराक में मिलिशिया समूह सीरिया में प्रवेश करेंगे या नहीं। यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दमिश्क में सैय्यदा ज़ैनब दरगाह जैसी जगहों पर क्या होता है।

हिंदी अनुवाद ; महेश कुमार ; सौजन्य पीपुल्स डिस्पैच

विश्व कविता

विश्व विख्यात अमेरिकन कवि कार्ल सैण्डबर्ग की एक कविता का अनुवाद

कार्ल सैण्डबर्ग

हथौड़ा

अनुवादक-मणिमोहन मेहता

मैंने देखा है
पुराने देवताओं को जाते
और नए देवताओं को आते हुए।

दिन - ब - दिन
साल दर साल
मूर्तियां गिरती हैं
और मूर्तियों का निर्माण होता है।

आज
मैं हथौड़े की पूजा करता हूँ।

दक्षिण कोरिया में जनता सडकों पर राष्ट्रपति तानाशाही लाने की जुगत में

नवउदार नीतियों के लिए जिन दो देशों को शुरूआती उदाहरण की तरह पेश किया जाता था उनमें से एक ब्राज़ील में पहले ही इन नीतियों का बाजा बज चुका था अब दक्षिण कोरिया में भी सरकार जनता के घेरे में है । यहाँ जब गुस्सायी जनता ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया तो अमरीका के पिट्ठू राष्ट्रपति यूं सेक येओल ने इमरजेंसी लगाने का एलान कर दिया। मगर लाखों लोग सड़को पर डटे रहे और यूं द्वारा देश में मार्शल लॉ लगाने के प्रयास को असफल कर दिया । इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, जिसे फिलहाल तो तिकड़म करके टाल दिया है मगर विपक्षी सांसदों ने यून के कार्यकाल के समाप्त होने तक महाभियोग के प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया है।

राजनीतिक नतीजों को देखते हुए, पीपीपी पार्टी के नेता हान डोंग-हून ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति की अब देश के मामलों में कोई भूमिका नहीं होगी, और यून के जल्दी इस्तीफे का वादा किया है। संसद में बहुमत रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस चाल को 'दूसरा तख्तापलट' करार दिया है, और राष्ट्रपति के अधिकार को हान को हस्तांतरित करने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया है।

महाभियोग पर मतदान की उम्मीद में शनिवार को लाखों दक्षिण कोरियाई लोग सड़कों पर उतर आए, और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। दस लाख से अधिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोरियाई ट्रेड यूनियन के महासंघ ने भी यून को पद से हटाए जाने तक अनिश्चितकालीन आम हड़ताल का आह्वान किया है। चूंकि कानून निर्माता, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर स्थिति अस्थिर बनी हुई है, इसलिए दक्षिण कोरिया के भविष्य के लिए एक अधिक लंबा संघर्ष शुरू होता दिख रहा है। यह समझने के लिए कि चीजें किस ओर जा सकती हैं, वर्तमान संकट की उत्पत्ति की जांच की जा रही है ।

ध्यान रहे कि दक्षिण कोरिया शीतयुद्ध के ज़माने से ही अमरीका का लग्गू भग्गू बना हुआ है और अभी भी उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ अड्डे की तरह काम कर रहा है ।

समाजवाद की परिभाषा

प्रभात पटनायक

बेरोजगारी से पैदा होने वाली आर्थिक वंचना से उबरने का एक उपाय यह हो सकता है कि बेरोजगारों की भी आय उतनी ही कर दी जाए, जितनी बारोजगारों की हो यानी बेरोजगारी भत्ते को, मजदूरी की दर के बराबर कर दिया जाए। लेकिन, निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में तो यह हो ही नहीं सकता है। बेरोजगारी की मौजूदगी, मजदूरों को अनुशासित करने के हथियार के रूप में काम करती है और यह सिर्फ पूंजीवाद के अंतर्गत ही नहीं होता है बल्कि हरेक ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है, जहां निजी क्षेत्र की उल्लेखनीय उपस्थिति हो। इसलिए, बेरोजगारों को बारोजगारों जितनी मजदूरी मिलना या दूसरे शब्दों में कहें तो बेरोजगारी भत्ते की दर, मजदूरी की दर के बराबर किया जाना, इस तरह की किसी भी अर्थव्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि इससे मजदूरों को अनुशासित करने का हथियार ही चला जाएगा। इस तरह की सूरत में तो काम से ''हटाए'' जाने का दंडात्मक प्रभाव ही खत्म हो जाएगा और ऐसा ही उस सूरत में भी होगा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में सचमुच पूर्ण रोजगार की स्थिति हो।

भारतीय संविधान की उद्देशिका से ''समाजवाद'' की संज्ञा को हटाने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, 22 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। पहली तो यह कि संविधान की उद्देशिका में समाजवाद की संज्ञा का उपयोग किसी जड़ सिद्धांत के अर्थ में नहीं किया गया है बल्कि उसका उपयोग तो महज एक कल्याणकारी राज्य के रूप में किया गया है, जो अपने सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता हो। और दूसरी बात यह कि इस अर्थ में ''समाजवाद'' हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यह कोई संविधान की उद्देशिका में जोड़ भर दी गयी चीज नहीं है बल्कि यह तो ऐसी चीज है जो इसके सार में समायी हुई है कि हम भारतीय गणराज्य को किस रूप में देखना चाहते हैं।

समाजवाद माने कल्याणकारी राज्य

मुख्य न्यायाधीश ''समाजवाद'' को एक संस्थागत रूप देने से परहेज करते हैं। दुनिया भर में ''समाजवाद'' की संज्ञा से यही अर्थ लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो और कम से कम उत्पादन के कुंजीभूत साधनों पर तो सामाजिक स्वामित्व अवश्य ही हो। लेकिन, भारत के मुख्य न्यायाधीश ''समाजवाद'' को स्वामित्व की संस्था के पहलू से परिभाषित करने के बजाए, परिणाम के पहलू से परिभाषित करते हैं और यह सुझाते हैं कि निजी उद्यम, ''समाजवाद'' के साथ बेमेल नहीं है। असली बात यह है कि एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जाए, जिसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की बराबरी सुनिश्चित हो।

समाजवाद की संस्थागत परिभाषा, जिसमें उसे उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के पहलू से परिभाषित किया जाता है, व्यापक पैमाने पर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि सामाजिक स्वामित्व को ऐसा कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें अवसर की समानता है, आवश्यक शर्त माना जाता है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश की बात का आशय यह था कि इस परिणाम को, सामाजिक स्वामित्व की संस्था के बिना भी हासिल किया जा सकता है। बेशक, समाजवाद का संबंध सिर्फ ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से ही नहीं है, जिसमें अवसर की समानता हो। उसका लक्ष्य इससे कहीं दूर तक जाता है। उसका लक्ष्य है, पूंजीवाद समाज में एटम की तरह अलग-अलग कर दिए गए व्यक्तियों के रूप में जो बिखराव लाता है, उस अवस्था का अतिक्रमण करने के जरिए, एक नये समुदाय का निर्माण। लेकिन, ऐसे नये समुदाय की पहचान में ऐसा कल्याणकारी राज्य भी शामिल है, जिसमें अवसर की समानता हो। नुक्ता यह है कि क्या ऐसा कल्याणकारी राज्य, जिसमें अवसर की समानता हो, उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के बिना हासिल किया जा सकता है।

बेरोजगारी के रहते अवसर की समानता नहीं

हमारा मानना है कि यह संभव नहीं है। फिर भी, निजी उद्यम और अवसर की समानता के बीच के अंतर्विरोध की कुछ स्वत:स्पष्ट मिसालों को उद्घृत करने के अलावा, हम यहां इस बहस में नहीं पड़ना चाहेंगे। इसके बजाए, हम तो सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह करेंगे कि अवसर की समानता के प्रति मुख्य न्यायाधीश की वचनबद्धता पर कायम रहे और इसकी पड़ताल करे कि अवसर की समानता के लिए किस तरह के समाज की जरूरत होगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शायद यह तो कोई भी नहीं कह सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज, जहां एक छोर पर संपदा का संकेंद्रण बढ़ रहा है और दूसरे सिरे पर बेरोजगारी तथा पोषणगत गरीबी बढ़ रही है, अवसर की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन, तब सवाल यह उठता है कि अवसर की समानता की ओर इस तरह की प्रगति की क्या निशानियां हैं?

साफ है कि एक ऐसी दुनिया में जहां बेरोजगारी हो या मार्क्स के शब्दों में श्रम की सुरक्षित सेना मौजूद हो, अवसर की कोई समानता नहीं हो सकती है। बेरोजगारों की आमदनियां, बारोजगारों से काफी कम होती हैं, फिर भले ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा हो। इसलिए, बेरोजगारों के बच्चों को तरह-तरह की वंचनाएं झेलनी पड़ रही होंगी, जिससे उनके और बाकी लोगों के बच्चों के बीच अवसर की समानता एक असंभव सी बात हो जाएगी।

बेरोजगारी से पैदा होने वाली आर्थिक असमानता के अलावा, बेरोजगारी से जुड़ा कलंक, बेरोजगार व्यक्ति में अपनी निरर्थकता का एहसास भी पैदा करता है, जो अनिवार्य रूप से बेरोजार व्यक्ति की संततियों के बचपन को एक प्रकार के अपघात का शिकार बना देता है। इस तरह के अपघात को, जिसे मिटाना अवसर की समानता के लिए जरूरी है, उसी स्थिति में मिटाया जा सकता है, जब बेरोजगारी को ही मिटा दिया जाए।

निजी उद्योग के लिए बेरोजगारी जरूरी

बेरोजगारी से पैदा होने वाली आर्थिक वंचना से उबरने का एक उपाय यह हो सकता है कि बेरोजगारों की भी आय उतनी ही कर दी जाए, जितनी बारोजगारों की हो यानी बेरोजगारी भत्ते को, मजदूरी की दर के बराबर कर दिया जाए। लेकिन, निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था में तो यह हो ही नहीं सकता है। बेरोजगारी की मौजूदगी, मजदूरों को अनुशासित करने के हथियार के रूप में काम करती है और यह सिर्फ पूंजीवाद के अंतर्गत ही नहीं होता है बल्कि हरेक ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है, जहां निजी क्षेत्र की उल्लेखनीय उपस्थिति हो। इसलिए, बेरोजगारों को बारोजगारों जितनी मजदूरी मिलना या दूसरे शब्दों में कहें तो बेरोजगारी भत्ते की दर, मजदूरी की दर के बराबर किया जाना, इस तरह की किसी भी अर्थव्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि इससे मजदूरों को अनुशासित करने का हथियार ही चला जाएगा। इस तरह की सूरत में तो काम से ''हटाए'' जाने का दंडात्मक प्रभाव ही खत्म हो जाएगा और ऐसा ही उस सूरत में भी होगा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में सचमुच पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। इसलिए, एक ओर अवसर की समानता और दूसरी ओर, निजी उद्यम के बीच पहला अंतर्विरोध, बेरोजगारी के प्रश्न पर सामने आता है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश चाहे इससे सहमत हों या नहीं हों, कम से कम इतना तो उन्हें भी मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी की मौजूदगी, अवसर की समानता के रास्ते में एक बाधा है।

संपदा की असमानता हो तो अवसर की समानता कहां?

अवसर की समानता सुनिश्चित करने की दूसरी स्वत:स्पष्ट शर्त यह है कि उत्तराधिकार में संपदा हासिल होने के मौकों को पूरी तरह से खत्म किया जाए या कम से कम उसमें भारी कमी तो जरूर ही कर दी जाए। एक अरबपति के बेटे और एक मजदूर के बेटे के बीच अवसर की समानता कैसे मानी जा सकती है, जब अरबपति के बेटे को उत्तराधिकार में अपने पिता से अरबों रुपए मिलने जा रहे हों। वास्तव में पूंजीवादी अर्थशास्त्र तक, जो पूंजीपतियों के मुनाफों को और इसलिए संपदा को, उनमें किसी खास गुण की मौजूदगी का परिणाम मानता है, जो गुण दूसरों में नहीं होता है, संपदा के उत्तराधिकार का बचाव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह इस तरह का उत्तराधिकार तो उसकी इस दलील के ही खिलाफ जाता है कि 'संपदा, उसके धारक के किसी विशेष गुण का परिणाम' होती है। इसीलिए, ज्यादातर पूंजीवादी देशों में इस तरह की विरासत पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता है। जापान में इस कर की दर 55 फीसद है और अन्य प्रमुख देशों में 40 फीसद के करीब है। हैरानी की बात है कि भारत में ऐसी विरासत पर कोई कर ही नहीं लगता है, जो कि अवसर की समानता से ठीक उल्टा जाता है।

अवसर की समानता की तीसरी शर्त यह है कि विरासत की संपदा पर रोक लगाए जाने के अलावा संपदा के अंतर को भी कम से कम किया जाए। संपदा के साथ ताकत आती है, जिसमें राजनीतिक तथा सामाजिक ताकत भी शामिल है। और जिस समाज में ताकत या सत्ता के वितरण में असमानता हो, उसमें सब को समान अवसर मिल रहा हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसलिए, इसके अलावा कि संपदा के माता-पिता से बच्चों के लिए हस्तांतरण की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, माता-पिता के रहते हुए उनके बच्चों को उनकी संपदा के अनुचित बढ़त के रूप में, संपदा के प्रभावों को भी रोका जाना जरूरी है। और इसके लिए संपदा के अंतर को कम से कम किया जाना जरूरी है। और यही बात आय की असमानताओं पर भी लागू होती है; अवसर की असमानता सुनिश्चित करने के लिए इसे भी कम से कम किया जाना चाहिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजनिक और समान हों

चौथी स्वत:स्पष्ट शर्त यह है कि आर्थिक असमानता को, संतति की शैक्षणिक योग्यता या कौशल-प्राप्ति के आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए। यह इसका तकाजा करता है कि शिक्षा तथा कौशल-प्राप्ति तक सब को समान पहुंच हासिल होनी चाहिए और यह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के जरिए ही संभव है, जो श्रेष्ठतर स्तर का शैक्षणिक प्रशिक्षण या तो मुफ्त या बिल्कुल नाममात्र के दाम पर मुहैया कराए, जिस तक सभी को पहुंच हासिल हो सके। नव-उदारवाद के तहत हमारे देश में और अन्यत्र भी जो निजीकरण हो रहा है, जो छात्रों की विशाल संख्या को शिक्षा के दायरे से बाहर कर के अवसर की समानता का मजाक बना देता है, उसके विपरीत उच्च स्तर की और सबके लिए पूरी तरह से सुलभ सार्वजनिक शिक्षा को सार्वभौम बनाया जाना जरूरी है। वास्तव में इस तरह की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के रहते हुए भी, जब तक महंगी निजी शिक्षा संस्थाएं बनी रहती हैं, उनके साथ एक झूठी प्रतिष्ठा लगी रह सकती है, जो इस तरह की संस्थाओं से भर्तियों को आसान बनाने के जरिए, अवसर की समानता में पलीता लगा सकती है। इसकी काट यह सुनिश्चित करने के जरिए करनी होगी कि निजी संस्थाएं अगर बनी भी रहती हैं तो, उन्हें सार्वजनिक संस्थाओं से ज्यादा फीस लगाने की इजाजत नहीं दी जाए। संक्षेप में यह कि निजी संस्थाओं के रूप में सिर्फ दातव्य संस्थाओं की ही इजाजत होनी चाहिए।

पांचवीं शर्त का संबंध स्वास्थ्य देख-रेख से है और इसके मामले में भी ठीक ऊपर बताए तकाजे ही लागू होते हैं। सरकार के तत्वावधान में, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के जरिए उच्च स्तर की सार्वभौम स्वास्थ्य देख-भाल, जो पूरी तरह से मुफ्त हो या नाम मात्र की ही कीमत मांगती हो जिसका बोझ सब उठा सकते हों, अवसर की समानता के लिए एक आवश्यक शर्त है।

कल्याणकारी राज्य समाजवाद तो नहीं फिर भी स्वागत योग्य

ये अवसर की समानता सुनिश्चित करने की कुछ पूरी तरह से स्वत:स्पष्ट और फिर भी न्यूनतम शर्तें हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सोशल डैमोक्रेसी भी, जिसने विकसित पूंजीवादी देशों में कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया था और बेरोजगारी को न्यूनतम स्तर पर, (1960 के दशक के आरंभ में ब्रिटेन में 2 फीसद के करीब) रखने के लिए केन्सवादी मांग प्रबंधन का उपयोग किया था, न तो सच्ची अवसर की समानता सुनिश्चित कर पायी थी और न ही एक टिकाऊ उपलब्धि बनी रह पायी थी। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध और सत्तर के दशक के आरंभ के मुद्रास्फीतिकारी संकट ने इसका भट्ठा बैठा दिया। यह दिखाता है कि एक ऐसे समाज में जिसमें वर्गीय आधार पर विभाजन बना रहे, अवसर की समानता सुनिश्चित करना नामुमकिन है।

जिस मुद्रास्फीतिकारी संकट ने कल्याणकारी राज्य को निगल लिया, बेरोजगारी की ऊंची दर का परिणाम था और इसका भी परिणाम था कि पहले एक जमाने में उपनिवेशवाद के अंतर्गत विकसित दुनिया को, उसकी सीमाओं से दूर के देशों में प्राथमिक माल उत्पादकों पर जिस तरह का पूर्ण नियंत्रण हासिल रहा करता था, अब नहीं रह गया था। इस घटनाविकास ने वर्गीय टकराव को तीखा कर दिया और मुद्रास्फीति इसी का नतीजा थी। अवसर की सच्ची समानता एक ऐसे समाज में ही हो सकती है, जहां उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के चलते, वर्गीय विरोध नहीं रहते हैं।

बहरहाल, हमें इस मुद्दे पर बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अवसर की समानता वाला कल्याणकारी राज्य मुहैया कराने प्रति ही वचनबद्ध रहने दो। इस दिशा में किसी भी कदम का, भले ही वह समाजवाद तक नहीं ले जाता हो, सभी समाजवाद की कामना करने वालों द्वारा स्वागत किया जाएगा।

बाबरी से मुरादाबाद वाया रतलाम बाड़ाबंदी का अभियान

बादल सरोज

हादसे वक्त के गुजरने के साथ अपने आप बेअसर नहीं होते, जख्म खुद ब खुद नहीं भरते । इसका उलट जरूर होता है, गुनाह अगर सही तरीके से, बिना कोई रूरियायत किये हिसाब में नहीं लिए जाएं, तो उनके ढेर से उठने वाली सड़ांध सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाती अनगिनत बीमारियों के संक्रमण का जरिया बन जाती है । कभी-कभी तो इस कदर, इतनी चौतरफा व्याप्त हो जाती है कि नासमझ होना ही समझदारी और बीमार होना ही अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण माना जाने लगता है। यह कालखण्ड कुछ इसी तरह का होने लगा है। बाबरी मस्जिद के आपराधिक ध्वंस के बाद जो हुआ या योजना बनाकर सिलसिलेवार तरीके से जो किया गया, वह नित नए विषाणुओं के हमलों के रूप में दिखने लगा है । हिन्दू राष्ट्र की विस्फोटक परिकल्पना को सार्वदेशिक बनाने की यात्रा नीचे, एकदम नीचे सुरंगें बिछाकर, पलीते लगाने से शुरू कर दी गयी और मुरादाबाद से वाया रतलाम मुम्बई होते हुए पूरे देश को अलग-अलग घेरों में बांधने तक आ पहुंची है। खुदाई के महाअनुष्ठान का शंख पहले ही फूंका जा चुका था ; आगाज़ संभल की मस्जिद से शुरू होकर अभी अजमेर की दरगाह तक पहुंचा है । और कहां-कहां जाएगा यह वक्त बताएगा। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बेतुके फैसले की पूंछ पकड़ कर अब छोटी-मोटी अदालतें भी खुदाई अनुष्ठान में जुट गयी हैं और देश के संविधान, विधिमान्य कानूनों की आहुतियां देकर स्वाहा-स्वाहा किये जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश इस पर अपनी सील मुहर लगाने के लिए इतने तत्पर हुए पड़े हैं कि सारी दिखावटी गरिमा, लाज शरम खूंटी पर टांगकर विश्व हिन्दू परिषद् जैसे घोषित सांप्रदायिक संगठनों के खूंटे पर जाकर पगुरा रहे हैं और जो बोल रहे हैं उससे जो थोड़ी बहुत न्यायपालिका की विश्वसनीयता बची थी, उसकी भी आहुति दिए दे रहे हैं । अपने इस आचरण से अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में अब तक जो दबी-छुपी बांबियां थीं उनके ढक्कन खोल रहे हैं । संभल, अजमेर बड़े पूजा स्थल हैं, उनके साथ हुआ चर्चा में भी आ जाता है, छोटे-गांवों कस्बों में इस तरह की कारगुजारियां क्या कहर बरपा करेंगी इसकी कल्पना ही की जा सकती है ।

हाल में एक और पिटारा मुरादाबाद में खोला गया है। यहां के नवधनाढ्यों की एक हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले डॉ0 बजाज ने अपना मकान एक अन्य काबिल डॉक्टर दंपत्ति को बेच दिया। संयोग से यह दंपत्ति चिकित्सक होने के अलावा मुसलमान भी है। मकान का सौदा होते ही बाबेला शुरू हो गया। पहले महिलाओं का प्रदर्शन कराया गया। इसके बाद कुछ पुरुष इकट्ठा हुए और ज्ञापन वगैरा दिए गए । दावा किया गया कि यदि यहां मुस्लिम परिवार रहेगा तो इस से परेशानी होगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कहा गया कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति इस कालोनी में आकर बसे । यहां तक कहा कि हम कॉलोनी वालों ने तय कर लिया है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हम कॉलोनी का गेट नहीं खोलेंगे। इस बेहूदा विवाद पर प्रशासन का बर्ताब और भी चौंकाने वाला था। उसने इस सरासर गैरकानूनी, असामाजिक और असभ्यतापूर्ण मांग पर सख्ती के साथ पेश आने की बजाय 'दोनों पक्षों से बात करके रास्ता निकालने' का रास्ता चुना और रास्ता यह निकला कि मुस्लिम डॉक्टर दम्पत्ति को अपना खरीदा हुआ मकान छोड़कर जाने का रास्ता चुनना पड़ा। मुरादाबाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व वाले उत्तरप्रदेश में आता है। यह ठीक वही - घेट्टोआइजेशन - बाड़ाबंदी है जिसे कोई 90 साल पहले नाज़ी जर्मनी में हिटलर और उसके दस्तों ने आजमाया था ; उसके निशाने पर यहूदी थे, इनके निशाने पर फिलहाल मुसलमान हैं। 'दूसरे धर्मों के लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, सिर्फ हिन्दू ही रहेंगे' का आधार, नीचे से सुरंगें बिछाकर धर्माधारित राष्ट्र की दुष्ट परिकल्पना को व्यवहार में उतारने की कोशिश है।

आज मुरादाबाद की मकान खरीदी की घटना की वजह से जो विद्रूप तरीके से सामने आ गया, वो अचानक नहीं हुआ है । कुछ समय पहले मुम्बई की एक जैन - जो खुद धार्मिक अल्पसंख्यक हैं - बहुल हाउसिंग सोसायटी में भी यह सब इसी तरह खुलेआम हुआ था। मगर मूलतः यह गुजरात मॉडल है जहां पिछले कुछ वर्षों से इसे गांव-गांव करके कई गांवों और बसाहटों में, कहीं एलानिया लिखकर तो कहीं गुपचुप ही लागू किया गया है। मोदी जिसे अपना मानते हैं उस गुजरात में अनेक गांव ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को हिन्दू राष्ट्र घोषित ही कर दिया है। अपने गांवों के बाहर बड़े-बड़े बोर्ड्स लटकाकर उन पर लिख दिया है ''हिन्दू राष्ट्रनूं गांव में आपनूं हार्दिक स्वागत करे छे'' मतलब हिन्दू राष्ट्र के गांव में आपका हार्दिक स्वागत है !! यह एकाध दो गांवों तक सीमित मामला नहीं है, ऐसे अनेक गांव हैं और यह भी कि जैसा दावा किया जाता है कि यह गांव के कुछ उत्साही नौजवानों ने किया है वैसा नहीं है ; इन गांवों में 'हिन्दू राष्ट्र का गांव' होने की घोषणा करने वाले बोर्ड्स पर विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के नाम गुदे हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं कि ये तीनों संगठन किस के साथ जुड़े हैं । इसलिए, इन्हें स्थानीय स्वतस्फूर्तता मान लेना भुलावे में रहना होगा । यह वैसा ही झांसा है जैसा 6 दिसम्बर 92 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, अगले तीन दिनों में एक-एक करके दिए बयानों में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी और आरएसएस के तबके सरकार्यवाह, जो बाद में सरसंघचालक बने, राजेन्द्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने दिया था और इस कार्यवाही की निंदा करते हुए उसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था। यह ठीक वैसी ही झूठ बयानी है जो मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ समय पहले की थी कि 'हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना हमारा काम नहीं है ।' वे अपने इस कथन के प्रति कितने गम्भीर थे, यह इन दिनों उन्हीं के कुनबे द्वारा युद्धस्तर पर शुरू किये जा रहे खुदाई अनुष्ठान से साफ हो जाता है। यह सिर्फ देखने-सुनने में ही कर्कश और बुरा नहीं है, इसके जो नतीजे निकलने हैं वे इससे भी ज्यादा खराब होंगे । मानव समाज का निर्माण और सभ्यताओं का विकास, बंद बाड़ों से बाहर आने के बाद हुआ है, उसे फिर से अलग अलग बाड़ों में बंद करके आगे नहीं ले जाया जा सकता, पीछे ही लौटाया जा सकता है । भारतीय समाज के ढांचे में यह सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं है ; इसलिए कि आज जो तर्क मुसलमानों को लेकर दिए जा रहे हैं वे वही तर्क हैं जो हमेशा शूद्रों और अन्य कथित निम्न समझे जाने वाले समुदायों और स्त्रियों के बारे में दिए जाते रहे हैं और सिर्फ दिए ही नहीं, लागू भी किये जाते रहे हैं । यह सिर्फ कहासुनी भर की बात नहीं है, ये वे 'नियम' हैं जिन पर वह 'महान' बताई जाने वाली संस्कृति पली-बढ़ी है, जिसकी पुनर्बहाली इस कुनबे का अंतिम लक्ष्य है । आज भी भारत के गांव और ज्यादातर पुराने शहर, इसी तर्ज पर बसे हुए हैं । आज भी शूद्रों के घर गांव की दक्षिण दिशा में होते हैं और उन्हें दक्खिन टोला कहकर पुकारा जाता है । दक्षिण दिशा अत्यंत अशुभ दिशा मानी जाती है । मनुस्मृति सहित सभी वर्णाश्रमजीवी ग्रन्थ किसे, कहां, किस दिशा में बसाया जाना चाहिये का स्पष्ट प्रावधान करते हैं और चांडालों तथा शूद्रों के बाकी वर्णों के रहने के इलाके से दूर, दक्षिण दिशा में रहने को ही 'धर्मसम्मत' बताते हैं । वास्तुशास्त्र सहित कई ग्रन्थ तो और आगे बढ़कर भूमि को भी वर्ण के अनुरूप विभाजित करते हुए श्वेत वर्ण की कोमल भूमि को ब्राह्मणी भूमि, दिखने में थोड़ी लाल को क्षत्रिय भूमि, जिस मिट्टी का रंग पीला हो उसे वैश्य भूमि बताते हुए निर्धारित करता है कि जहां की मिट्टी काली हो , वही स्थान शूद्रों का है। वृहतसंहिता तो मकान के रंग और उसमे कमरों की संख्या भी तय कर कहती है कि शूद्रों के घर किसी भी हालत में 2 कमरों से अधिक के नहीं होने चाहिए । ये चंद याद आये उदाहरण हैं, ऐसे अनेक हैं । मुरादाबाद के नवधनाढ्य यदि सिर्फ हिन्दू धर्म के लोगों को ही अपने साथ रखने पर इस कदर जोर देंगे तो, उसी धर्मसम्मत व्यवहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिस के आधार पर वे अपना बाड़ा बनाने को आतुर हैं । बात जब शुरू होगी तो यहीं तक थोड़े ही रुकेगी।

यह न तो ज्यादा दूर की कौड़ी है ना ही अब कालातीत हो गयी बात है। नयी और आधुनिक टाउनशिप्स और कालोनियों में बसे लोगों का सामाजिक प्रोफाइल जांचेंगे तो आज भी विरले ही अपवाद मिलेंगे । कोलम्बिया यूनिवर्सिटी से पूरी डिग्री लेकर और लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से आधी पढ़ाई करके वजीफे के साथ हुए अनुबंध की शर्तें पूरी करने बड़ोदा राजघराने की नौकरी करने आये डॉ0 बीआर अम्बेडकर को अपनी जाति छुपाकर पारसी बनकर कमरा किराए पर लेना पड़ा था । बाद में जाति का पता लगने पर उन्हें घेरकर हमला करने की जो कोशिश हुई थी वह भी पुरानी कहानी नहीं है । बनारस में अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी का स्वास्थ्य देखने गए उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम के वापस लौटने पर पंडित जी ने अपने घर का शुद्धीकरण किस तरह किया था, यह भी कोई पाषाणकालीन घटना नहीं है । अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने के बाद नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस में प्रवेश करने से पहले उसके इंच-इंच को गंगाजल से धुलवाकर किस तरह 'पवित्र' किया था, यह तो अभी-अभी, 2017 की ही बात है। मुरादाबाद में मुस्लिम डॉक्टर के बहाने जो बाड़ाबंदी - घेट्टोआइजेशन - किया जा रहा है वह अंत में यहीं तक पहुंचने वाला है।

जिन महिलाओं को आगे करके यह एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा था उन्हें शायद ही इसका भान होगा कि इस बाड़े में भी एक दड़बा होना है, जो ख़ास उन्ही के लिए होगा। उन्हें नहीं पता कि उनके गले में ये किस की आवाज है। वे नहीं जानतीं कि जो उन्हें इस प्रदर्शन के लिए बैनर छपवा कर दे रहे हैं, उनके पास अगले बैनर्स भी तैयार रखे हैं जिनमें महिलाओं की हद और सीमाएं निर्धारित की जाने वाली हैं । पैकेज आता है तो अधूरा नहीं आता पूरा ही आता है।

इस तरह के पैकेजों के थोक व्यापारी नौसिखिये नहीं हैं। वे जानते हैं कि दारुण दुन्ख देने से पहले मति हर लेना, बुद्धि और विवेक का हरण कर लेना जरूरी होता है । गुजरात के जिन गांवों का जिक्र ऊपर किया है, उनमें भीतर घुसकर देखने पर पता चलता है कि खाना पकाने के लिए स्त्रियां जंगल से लकड़ियां बीनकर ला रही हैं क्योंकि रसोई गैस इतनी महंगी हो गयी है कि उज्वला का सिलेंडर भरवाना उनके लिए संभव नहीं है ; रोजगार की आस में युवा या तो निठल्ले घरों में बैठे हैं या नाममात्र की मजूरी में 12-12 घंटे किसी ठेकेदार की अस्थायी नौकरी में खट रहे हैं। मगर इस सबके बाद भी गांव को हिन्दू राष्ट्र बनाने में खुश हैं और चाय वाले मोदी के बाद गाय वाले योगी के आने की उम्मीद से तर बैठे हैं। खुद के जीवन की उलझनों से खीजे हुए हैं और उससे उपजी चिढ़ को रतलाम में 6, 9 और 11 साल के मासूम बच्चों को पीट-पीटकर और उनसे जयश्रीराम बुलवाकर निकाल रहे हैं ; अपनी कुंठा को इस तरह बहला-सहला रहे हैं। कवि धूमिल की उपमा में कहें तो एक आदमी पीट रहा है, दूसरा उसका वीडियो बना फोटू खींच रहा है, तीसरा आदमी इन्ही के पसीने और लहू से अपनी राजनीति की फसल सींच रहा है। ये तीसरा आदमी कौन है ? इस तीसरे की शिनाख्त करने का सलीका सिखाने के जरिये ही समाज को बाड़ों में बंद करने और सभ्यता के अब तक के हासिल को कुंद करने की साजिशों को विफल किया जा सकता है ।

न्यायमूर्ति ?

मनोज कुलकर्णी

भारत को आजाद हुए सतहत्तर साल हो चुके। हमारा संविधान लागू हुए भी सात दशक से अधिक बरस बीत गये। जिसमें 'हम भारत के लोगों' ने अपने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का वायदा किया है। ऐसा लोकतंत्र, जिसमें सारे नागरिक समान होंगे। धर्म, जाति, रंग, लिंग, भाषा, भूषा या भूगोल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसीलिए, जनतंत्र में अदालतें खासी महत्वपूर्ण होती है। जिन पर संविधान द्वारा नागरिकों को दी गयी ग्यारंटी की हिफाजत की जिम्मेदारी हुआ करती है।

अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए अदालतें न्यायाधीशों पर निर्भर करती हैं। स्वाभाविक ही आम नागरिकों की तुलना में 'न्यायमूर्तियों' से अधिक संयमित और संतुलित जीवन की 'अपेक्षा' की जाती है। विशिष्ठ और गरिमामय संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अपने पूर्ववर्तियों के आदर्श आचरण और उच्च मानवीय गुणों से स्थापित होती गयी अलिखित नैतिक परम्पराओं का भी दृढ़ता से पालन करेंगे। सार्वजनिक जीवन में उनसे कुछ मर्यादाओं के पालन की भी अपेक्षा की जाती है। जिनका ध्यान दिलाते रहने के लिए ही समय-समय पर विभिन्न संहिताएं तैयार की जाती हैं। न्यायाधीशों के लिए भी आचार-संहिताएं हैं। माना जाता है कि वे सार्वजनिक राजनीति और राजनेताओं से पर्याप्त दूर रहेंगे।

अक्सर कह दिया जाता है कि आखिर न्यायाधीश भी हाड़-मांस के मनुष्य हैं। उनके अपने निजी विचार, आस्थाएं, भावनाएं, आग्रह-दुराग्रह और नजरिये हो सकते हैं। निश्चित ही होते होंगे, किंतु पद स्वीकारते समय ली गयी शपथ उन्हें अनके 'मर्यादाओं' से बांध देती हैं। कभी-कभी कुछ अदालती फैसले अथवा न्यायमूर्तियों की टिप्पणियां, सार्वजनिक जीवन में न्यायाधीशों की उपस्थिति और उनका आचरण, कानून की स्थापित मान्यताओं, आदर्श संहिताओं और संविधान की शपथ का उल्लंघन किये जाने तरफ इशारा करते हैं, तब विवाद उठ खड़े होते हैं।

विगत दिनों इलाहाबाद हायकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ऐसी ही हरकत की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा भाषण दिया, जो न केवल आपत्तिजनक बल्कि नफरती कहा जाना चाहिये। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में विवादित कट्टरपंथी संगठन 'विश्व हिंदू परिषद' के कानून-प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 'समान नागरिक संहिता-एक संवैधानिक जरूरत' जैसे नाजुक मसले पर बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने जो कहा, प्रमाण है कि हमारी न्याय-व्यवस्था में संकीर्ण धार्मिक दुराग्रह कितने भीतर तक घुस चुके हैं?

करीब आधा घंटा बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के बारे में अनेक आपत्तिजनक बातें कहीं। चार शादियों, तीन तलाक और हलाला जैसे मसलों पर बोलते-बोलते वे 'हम और वो' अर्थात 'हिंदू-मुसलमान' वाली विवादास्पद भाषा-शैली का प्रयोग करते रहे। उनका कहना था कि हिंदुओं में जन्म लेने के साथ बच्चों को धार्मिक संस्कार दिये जाते हैं, जबकि मुसलमान बच्चों के सामने पशुओं की हत्या करते है, तब वे सहिष्णु कैसे बन सकते हैं? उनका मानना है कि भारत में बेहतर काम करने वाले हिंदू ही कहे जाने चाहिये, फिर उनकी पूजा-पद्धति चाहे जो हो। जस्टिस यादव यह भी मानते हैं कि हिंदू ही इस देश को विश्वगुरू बना सकते हैं।

देश को बहुसंख्यकों के अनुसार चलाया जाना चाहिये, ऐसा कहने वाले जस्टिस यादव का कानून और संविधान में कितना भरोसा होगा, समझा जा सकता है। रामलला को आजाद कराने के लिए पूर्वजों की कुर्बानी के प्रशंसक और राममंदिर अपनी आंखों से देख लेने के सुख से भावविभोर जस्टिस गाय को राष्ट्रीय-पशु बना देने और 'भगवान राम के सम्मान' में कानून बनाने की वकालत तो पहले ही कर चुके हैं। वे 'कठमुल्लों' से देश को सावधान रहने के लिए भी आगह करते सुने गये। ऐसी कट्टर सोच रखने वाला हायकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश इंसाफ कैसे करता होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण का संज्ञान लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।

कहते हैं न्याय दे देना भर पर्याप्त नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिये। कानून-देवी की एक सर्वज्ञात छवि रही है। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथों में तराजू वाली। सुप्रीम-कोर्ट के पिछले प्रधान-न्यायाधीष जस्टिस चंद्रचूड़ ने वह पट्टी हटवा दी थी। देश की खस्ताहाल कानून-व्यवस्था, प्रमुख संवैधानिक मुद्दों को सुप्रीम अदालत द्वारा लटकाये रखने, कपड़ों से आतंकी को पहचानने वाले बड़बोले प्रधानमंत्री, बुल्डोजर दौड़ाते मुख्यमंत्रियों, सड़क छाप भाषा बोलते मंत्रियों-सांसदों, पक्षपाती राज्यपालों, बंधुआ बन चुके चुनाव-आयोग, ईडी-सीबीआई-आयकर विभागों और जस्टिस यादव जैसों को कानून की देवी अपनी खुली आंखों से देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी?

कामरेड के एम तिवारी

कामरेड के एम तिवारी नहीं रहे, 10 दिसम्बर की सुबह उनका निधन हो गया। वे सीपीएम की केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे और पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव रहे थे। सुबह उनका निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों से वह बहादुरी के साथ कैंसर से लड़ रहे थे। वे सत्तर वर्ष के थे।

कामरेड तिवारी एक ट्रेड यूनियन नेता थे, जो गाजियाबाद-साहिबाबाद औद्योगिक पट्टी में काम करते हुए, साधारण कार्यकर्ताओं की कतारों में से निकल कर आए थे। वह सीटू के दिल्ली राज्य सचिव रहे थे और वर्षों तक सीटू की जनरल काउंसिल और वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे कारखानिया मजदूर से मजदूर वर्ग के नेता बनने के पाठ्यपुस्तक - टेक्स्ट बुक - उदाहरण भी हैं। स्वदेशी पॉलीटैक्स कारखाने के मजदूर के नाते यूनियन में आये, यूनियन बनाने और लड़ने के चलते बर्खास्त हुए और उसके बाद मजदूरों को लड़ना सिखाते, उन्हें संगठित करते हुए मजदूर वर्ग की पार्टी - सीपीआई (एम) - के नेतृत्व के शीर्ष तक पहुंचे।

1977 में पार्टी में आए कामरेड तिवारी 1988 में पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी में, 1991 में राज्य सेक्रेटेरियट में और 2018 में केंद्रीय कमेटी में चुने गए थे।

अपने राजनीतिक कार्य के दौरान उन्होंने तीन महीने से ज्यादा जेल में गुजारे थे और उन्हें तीन साल नौ महीने भूमिगत रहना पड़ा था।

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद में मजदूर आन्दोलन, खासकर सीटू की अगुआई में हुए संघर्षो ने जो इतिहास बनाए हैं उन्हें कितने एमपी, कितने एमएलए की कसौटी पर नहीं उसके अपने क्षेत्र से बाहर देशव्यापी पैमाने पर हुए प्रभाव से आँका जाना चाहिये ; इनमे 13 लाख मजदूरों की वह शानदार हड़ताल भी शामिल है जिसने पूरे देश के मजदूरों को मिनिमम वेज की लड़ाई के लिए प्रेरणा दी, उनके सामने जीत का उदाहरण पेश किया। कामरेड के एम तिवारी इस हड़ताल के नेताओं में से एक थे।

सीपीएम के पोलिट ब्यूरो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है 11 दिसम्बर की सुबह सुरजीत भवन से उन्हें अंतिम विदाई दी गयी।

पेज 9 का शेष

वो सीताराम.....

सकते थे, खासकर अगर वे केरल के व्यंजन हों और मांसाहारी हों। वे हर निवाले में स्वाद को समझते हुए उसे थोड़ा-थोड़ा करके खाते थे। वे अभी भी पहले व्यंजन का आनंद ले रहे होते थे, जबकि आप लगभग सब कुछ खा चुके होते थे। एक बार केरल में एक बैठक के दौरान पुट्टू और मछली करी का लुत्फ़ उठाते हुए उन्होंने पाया कि पुट्टू की उत्पत्ति पुर्तगालियों से हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीलंका में भी पुट्टू पाया जाता है। यहां तक कि जब भोजन एकेजी भवन के दफ्तर के मेस जैसा सीमित होता था, तब भी वे उसका स्वाद लेने में अपना समय लगाते थे। हर चीज में बारीकियाँ ढूँढ़ने की उनकी एक अनोखी आदत थी और वे एक पूर्णतावादी भी थे।

जब भी उनके पास कोई मिलने वाला आता था, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित क्यों न हों, वे हमेशा अपने सहयोगियों का परिचय ज़रूर करवाते थे, चाहे वे पार्टी में किस भी स्तर पर क्यों न हों। हममें से जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो विस्तार से मिनट्स लिखते थे। उनके गोलघुमावदार लेखनी में नोट पढ़ने में बहुत मज़ेदार होते थे। मैंने सिर्फ़ एक और व्यक्ति को ऐसा करते देखा है, वे हैं कॉमरेड पिनरई विजयन।

हालाँकि हममें से किसी को भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन सीताराम को पता था कि जब उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, तो उनके साथ क्या होने वाला था। यह ऐसी चीज है जो हममें से कई लोगों को जीवन भर परेशान करेगी।

लेकिन फिर, वह सीताराम थे, जिनकी मनमोहक मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन वह जीवन का भरपूर आनंद लेने में विश्वास करते थे, इसके परिणामों की परवाह किए बिना। सब कुछ से अलग, वह एक इंसान थे, प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले, साथ ही कभी-कभी डरपोक और कमज़ोर भी। वह उत्पीड़ितों के लिए महसूस करते थे; उनके साथ समान रूप से दुखी और खुश होते थे।

वह सीताराम थे! लाल सलाम सीताराम!

सुभाषिणी अली, डा.अशोक ढवले, आर अरुण कुमार, डा. विक्रम सिंह की मौजूदगी में होगा

15 से 17 दिसंबर तक महू में माकपा का राज्य सम्मेलन

भोपाल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 17 वां राज्य सम्मेलन 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में होने जा रहा है।

सम्मेलन की शुरूआत ड्रीमलैंड चौराहे पर एक विशाल आमसभा के साथ होगी। पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्या और पूर्व सांसद सुभाषिणी अली, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के नेता, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पोलित ब्यूरो के सदस्य डा. अशोक ढवले, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य व खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डा. विक्रम सिंह सहित प्रदेश के नेता इस सभा को संबोधित करेंगे।

सभा स्थल का नाम महू क्षेत्र के संघर्षशील नेता कामरेड चांद खां की स्मृति को समर्पित किया गया है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इस सम्मेलन स्थल का नाम आदिवासी विद्रोह के नेता टंटिया मामा के नाम रखा गया है। सम्मेलन में पार्टी के पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्या सहित दिवंगत नेताओं का स्मरण किया जाएगा। सम्मेलन का मंच महू के किसान नेता केशर सिंह मालवीय की स्मृति को समर्पित है।

स्वागत समिति के अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल नागर महासचिव अरुण चौहान और कोषाध्यक्ष कैलाश लिंबोदिया के अनुसार सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

सम्मेलन में प्रदेश भर के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पिछली गतिविधियों की समीक्षा के साथ ही प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करते हुए उसमें प्रभावी हस्तक्षेप को सुनिश्चित कर मेहनतकश तबकों के पक्ष में तबदील करने की योजना बनाई जाएगी। सम्मेलन में मेहनतकश आवाम की एकता का निर्माण करने के साथ ही संगठन का विस्तार करने की भी योजना तैयार की जाएगी।

सम्मेलन के अंतिम दिन राज्य समिति व नए नेतृत्व का भी निर्वाचन किया जाएगा। साथ ही पार्टी की 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी किया जाएगा।

20 दिसम्बर से प्रदेश भर में केरल के साथ एकजुटता

वाम सरकार की उपलब्धियों और भाजपा की साजिशों को लेकर जनता के बीच अभियान

भोपाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विपरीत, केरल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार जन-समर्थक नीतियां लागू कर रही है। जहां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में व्यवसायीकरण और कट्टरपंथ थोप रही हैं, वहीं केरल में वाम मोर्चा सरकार के काम किसान मजदूरों के कल्याण पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने राज्य के विकास को अस्थिर करने और केरल के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय फंड्स को रोक कर रखा है, जब कि कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भी कटौती की गई है। मोदी सरकार बजट का अभाव पैदा करने और केरल सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। देश की मेहनतकश जनता के संगठन 20 दिसंबर से 31 दिसम्बर तक गाँव, बस्ती और शहरों में जाकर केरल की वाम जनवादी मोर्चा सरकार के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशों को बेनकाब करेंगे तथा केरल सरकार की शानदार उपलब्धियों के बारे में बताएँगे।

अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, खेत मजदूर यूनियन ने देश भर में 'केरल एकजुटता अभियान' चलाकर वहाँ की वाम जनवादी मोर्चा की सरकार की वैकल्पिक नीतियों को आम नागरिकों के बीच ले जाने और वैसी ही नीतियाँ देश भर में बनाए जाने की मांग उठाने का आह्वान किया था। इसी के तहत मध्यप्रदेश में इसे दिसम्बर के अंतिम 11 दिन चलाया जाएगा । हर जिले में एक या अधिक स्थानों पर किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, सीटू, मध्यप्रदेश में आदिवासी एकता महासभा भी, मिलकर सभा, सेमिनार आयोजित करने - इनमें केरल सरकार की उपलब्धियों और वैकल्पिक नीतियों को रखते हुए मोदी अडानी गठबन्धन द्वारा इस सरकार के खिलाफ की जा रही साजिशों को बेनकाब करते हुए वाम जनवादी मोर्चा सरकार के प्रति एकजुटता व्यक्त की जायेगी।

इसलिए... राजेन्द्र शर्मा

बच्चे तीन ही अच्छे!

भागवत जी, आपने बचा लिया। वर्ना ये देश तो बस डूबने ही वाला था। माना कि मरने वाले पहले से कम मर रहे थे, पर पैदा होने वाले तो और भी कम पैदा हो रहे थे। सो आबादी घटती जा रही थी। बूढ़ों की आबादी बढ़ती जा रही थी। वह दिन दूर नहीं था जब देश में सिर्फ बूढ़े रह जाते और धीरे-धीरे वो भी मर-खप जाते। भारतवर्ष ही मिट जाता। पर आपने एक छोटा सा सूत्र देकर बचा लिया--बच्चे तीन ही अच्छे। बच्चे कम से कम तीन बनाओ, भारत को दुनिया में नंबर वन बनाओ!

हमें पता है कि हुज्जत करने वाले भागवत जी के देश की रक्षा के इस फार्मूले पर भी हुज्जत करेंगे। और कुछ नहीं तो गिनती का ही टंटा खड़ा करेंगे। कहेंगे कि भागवत जी को यह गिनती कहां से मिली कि आबादी घट रही है। लेकिन, आबादी का घटना या बढ़ना क्या सिर्फ गिनती का मामला है। सिर्फ गिनती से डैमोक्रेसी चलती है, देशों की आबादियां नहीं चला करती हैं। देश विश्वासों से, आस्थाओं से चलते हैं। देखा नहीं कैसे बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक हिंदुओं की आस्था से चला। जो मस्जिद सबने देखी थी, पहले ढांचा बनी, फिर गायब हो गयी और जो राम मंदिर किसी ने नहीं देखा था, भव्य सचाई बन गया। असली चीज है विश्वास। अब संघ का विश्वास है कि आबादी घट रही है, तो आबादी घट रही है। जैसे हाथी के पांव में सब का पांव, वैसे भागवत जी के विश्वास में मोदी जी का विश्वास, उनकी सरकार का विश्वास। और होने को तो हो सकता है कि आखिर में उनकी जनगणना का भी भागवत जी के विश्वास में ही विश्वास निकल आए। इसीलिए तो जनगणना नहीं करा रहे हैं; आबादी जरा अच्छी तरह से घट ले, जिससे गिनती का भागवत जी के विश्वास से मेल बैठ जाए। वर्ना गिनती ही एंटी-नेशनल कहलाएगी, भागवत जी तो अपने विश्वास से टस से मस होने से रहे। बच्चे तो तीन ही अच्छे रहेंगे।

और ये भागवत जी, मोदी जी, योगी जी आदि, आदि से तीन बच्चों की डिमांड की दुष्टता बंद होनी चाहिए। भागवत जी की डिमांड कम से कम तीन बच्चों की है, ज्यादा से ज्यादा तीन की नहीं। जो तीन से फालतू होंगे, वो बच्चे इन राष्ट्र निर्माताओं के हिस्से की भरपाई करेंगे। और हां! इसमें हिंदू-मुस्लिम करने का इल्जाम भागवत जी पर कोई नहीं लगा सकता है। मुसलमान भी करें तीन या ज्यादा बच्चे पैदा, संघ क्या रोकता है? बस हिंदू तीन से कम बच्चे ना करें। और हां! मुसलमान, तीन से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करें। और हिंदू बच्चे तीन ही क्यों? मां-बाप और अडानी जी की सेवा में एक-एक बच्चा लग जाएगा, तो हिंदू त्योहारों पर मस्जिदों के आगे तलवार कौन लहराएगा?

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संध्या शैली द्वारा **जेयन आफसेट वर्क्स** 119 इनारा हाउस, पुल बोगदा रायसेन रोड भोपाल मप्र से मुद्रित होकर 13बी पद्मनाभ नगर, भोपाल **462023** से प्रकाशित। फोन: 2757751, **संपादक:** बादल सरोज, **कार्यकारी संपादक:** रामप्रकाश त्रिपाठी, **संपादक मंडल** संध्या शैली, प्रमोद प्रधान, उपेन्द्र यादव
प्रबंध संपादक : सुरेन्द्र जैन 9200618795 **Email: lokjatan@gmail.com**